सत्यमेव जयते
नीति आयोग

नीति कार्यपत्र

समावेशी विकास का भारतीय मॉडल: सबका साथ सबका विकास

अरविंद विरमानी

दिसंबर 2023

समावेशी विकास का भारतीय मॉडलः सबका साथ सबका विकास

अरविंद विरमानी[1]

क. प्रस्तावना

भारत ने घरेलू और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद लगातार विकास दर्ज की है, जिसमें सदी में एक बार होने वाली कोविड-19 और उसके बाद तेल की कीमत का झटका शामिल है। भारतीय नीति निर्माताओं को प्रेरित करने वाले कई विचार भी विकसित देशों और विश्व भर में स्वीकृति प्राप्त कर रहे हैं। भारत की स्वदेशी विकास रणनीति स्थिर नहीं रही है, लेकिन अनुभव और बदलते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के साथ उभरी और विकसित हुई है। इसलिए इस विकास मॉडल को औपचारिक रूप देने के प्रयास के लिए यह एक उचित समय है। पहले के दो वर्किंग पेपर [विरमानी (2022क, ख)] में "समावेशी विकास के भारतीय मॉडल: सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" की रूपरेखा तैयार की है। इस पेपर में डेटा के साथ अवधारणाओं को विस्तृत किया है, परिणामों का एक अस्थायी विश्लेषण करता है, और मॉडल के भविष्य के विकास के बारे में कुछ परिकल्पनाओं के साथ समाप्त होता है।

भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि "इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का एक संघ होगा," जिसमें भारत गणराज्य के लिए "इंडिया" और "भारत" को समान रूप से आधिकारिक लघु नामों के रूप में संहिताबद्ध किया है। यह हमारे सभ्यतागत इतिहास में स्थापित है, जिसमें प्रोटो-गणतंत्र जनपद और महा-जनपद शामिल थे। हमारी सदियों पुरानी संस्कृति आर्थिक और सामाजिक विकास के हमारे दृष्टिकोण को भी प्रभावित करती है। इस संस्कृति का एक प्रासंगिक पहलू सभी की आर्थिक और सामाजिक भूमिका में परिवार और समुदाय का महत्व है। परिवार की स्थिरता एक सभ्यतागत लक्ष्य है और अब इसे उच्च घरेलू बचत दर में व्यक्त किया गया है। अनाज के उच्च अनुपात और मांस के कम अनुपात वाला आहार भी सभ्यता की स्थिरता से संबंधित है। इसी प्रकार, व्यापार, उत्पादन और निवेश में समुदाय की पारंपरिक भूमिका उद्यमिता, पूंजी जुटाने और जोखिम लेने में समर्थन प्रदान करता है। व्यक्तिगत अधिकारों और परिवार/सामुदायिक जिम्मेदारियों का संतुलन समय और स्थान के साथ विकसित हुआ है लेकिन उसका महत्व बरकरार है। यह संविधान में राष्ट्र के संबंध में नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के रूप में भी परिलक्षित होता है।

अगला खंड (ख) समावेशी विकास और विकास मॉडल का अवलोकन प्रदान करता है और इसके पहले स्तंभ बाजार अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय दृष्टिकोण पर विस्तार प्रदान करता है। इसमें आगे आर्थिक

---

[1] लेखक नीति आयोग के सदस्य हैं।

विकास को बढ़ावा देने के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान किए गए कुछ आर्थिक सुधार प्रस्तुत किए हैं। तीसरा खंड (ग) समाज कल्याण के लिए भारतीय दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है। चौथा खंड (घ) आर्थिक विकास के भारतीय मॉडल के तीसरे स्तंभ पर केंद्रित है, जिसमें मैक्रो-आर्थिक विचार-विमर्श और परिणामों की जटिलता के प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण, और आर्थिक विकास और समावेशी विकास में अंतर्निहित सामाजिक गतिशीलताओं के बारे में उल्लिखित है। उप-खंड मुद्रास्फीति, निवेश और उत्पादकता और व्यापार एवं औद्योगिक नीति जैसे कई पहलुओं की खोज करते हैं। खंड (ङ) अगले कुछ दशकों में मॉडल के विकास के लिए संभावित दिशा की परिकल्पना करता है। खंड (च) में पेपर समाप्त होता है। पेपर के अंत में संदर्भों के बाद एक शब्दावली है और नीतिगत सुधारों और कार्यक्रमों को सूचीबद्ध करने वाले परिशिष्ट हैं।

ख. मॉडल

समावेशी विकास का भारतीय मॉडल एक खुली, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में स्थापित है, जो "कैच-अप विकास" और लोकतांत्रिक सामाजिक विकास से गुजर रहा है। सरल शब्दों में, नीति और संस्थागत सुधार, और सार्वजनिक वस्तुओं और अर्ध-सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान, निजी निवेश, मानव और सामाजिक पूंजी विकास को चलाते हैं, जो बदले में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और उत्पादकता को बढ़ाते हैं। प्रयास एक उचित चक्र शुरू करने का है जिसमें नागरिकों का सशक्तिकरण और सभी के लिए अवसर की समानता, समावेशी विकास को प्रेरित करता है, जो आगे सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए राजस्व उत्पन्न करता है। मॉडल के तीन स्तंभ हैं: (1) बाजार अर्थशास्त्र, (2) सशक्तिकरण, और (3) समग्र दृष्टिकोण।

स्तंभ 1: इंडिक बाजार अर्थव्यवस्था

इंडिक बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता समावेशी विकास और सामान्य जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निजी उद्यम और बाजार अर्थव्यवस्था की भूमिका और चुनिंदा सरकारी हस्तक्षेप के बीच संतुलन है। यह एक खोज है जो दशकों पहले शुरू हुई थी, लेकिन पिछले दशक में कम मध्यम आय वाले देश (एलएमआईसी) के लिए इष्टतम संतुलन प्राप्त करने के लिए परिष्कृत की गई है।

निजी पहल और प्रतिस्पर्धा विकास और लाभकारी रोजगार के चालक हैं। राष्ट्र के आर्थिक जीवन, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और बिक्री और रोजगार सृजन/उत्पन्न करने में व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी प्रकार के व्यवसाय इस आर्थिक जीवन का हिस्सा हैं: कंपनियां, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, स्वरोजगार, पारंपरिक और आधुनिक, घरेलू और विदेशी व्यवसाय।

सरकार आर्थिक और सामाजिक वातावरण बना रही है और बनाती रहेगी, ताकि इस विशाल और विविध उप-महाद्वीप के प्रत्येक क्षेत्र, भूगोल में रहने वाले प्रत्येक समुदाय, सामाजिक और सामाजिक-आर्थिक समूह में ऐसी उद्यशीलता पनप सके और विकसित हो सके।

अनुभव से पता चलता है कि संसाधनों और आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर सरकार का एकाधिकार अक्षम है, क्योंकि सरकार की प्रकृति और प्रोत्साहन संरचना अनिवार्य रूप से जोखिम से बचने के व्यवहार की ओर उन्मुख है जो उद्यमशीलता/नवाचार के विपरीत है। "सरकार के पास व्यवसाय में होने का कोई कार्य नहीं है", और "न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन", ऐसे वाक्यांश हैं जो इस बिंदु के सही अर्थ समझाते हैं। जब तक अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका सावधानीपूर्वक चयनित क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, तब तक इसका परिणाम निजी पहल और गतिविधि से बाहर होने का रहेगा, जो सामान्य रूप से अधिक प्रभावी, कुशल और टिकाऊ होती है। सतत, समावेशी विकास प्रमुख उद्देश्य है; दीर्घकालिक निवेश और विकास को कम करने के लिए अल्पकालिक अत्यावश्यकताओं को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जाता है।

निजी सामाजिक पहल (एनपीओ, एनजीओ) लोकतंत्र का एक स्वागत योग्य और आवश्यक भाग हैं, क्योंकि ऐसे सामाजिक संगठन उन क्षेत्रों में जनता का पूरक और समर्थन कर सकते हैं जिनमें सामुदायिक स्तर पर मानवीय, व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता होती है। सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है और उसे प्रदान करना भी चाहिए, लेकिन नौकरशाही आम तौर पर अनाथ, दिव्यागजन, मानसिक रूप से विक्षिप्त, विधवाओं और वृद्ध जनों जैसे व्यक्तिगत, भावात्मक और सामाजिक संपर्क की आवश्यकता वाले लोगों को निरंतर सहायता प्रदान करने में बहुत प्रभावी नहीं होती है। स्थानीय समुदायों से जुड़े व्यक्ति अथवा गैर सरकारी संगठन ऐसा करने के लिए बेहतर स्थिति पर हैं। इसके अलावा, गैर सरकारी संगठन और एनपीओ उन क्षेत्रों में सरकार का पूरक भी हो सकते हैं जहाँ वह समाज के कम सुविधा वाले सदस्यों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में अप्रभावी या अक्षम है।[2]

यह दृष्टिकोण लचीला और बाजार अर्थशास्त्र के अनुरूप है, लेकिन बाजार की विफलता, बाहरी कारक, सूचना विषमता और सीमित समझदारी के कारण अधिक चिंता भी है।[3] विशेष रूप से, इस दृष्टिकोण में (क) बाजार प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार (ओलिगोपॉली) और एकाधिकार (मोनोपॉली)[4] (ख) सार्वजनिक और कल्याणकारी अर्थशास्त्र: सरकार और बाहरी कारकों द्वारा सार्वजनिक माल का प्रावधान [अवसंरचना में सुनिश्चितता, सरकारी प्रोत्साहन या सब्सिडी की आवश्यकता और नकारात्मक बाहरी कारकों (प्रदूषण) को

---

[2] उदाहरण के लिए, सेवा ने 1970-1990 के दौरान महिलाओं को रोजगार कौशल प्रदान किया और विपणन सहायता प्रदान की।

[3] सीमित समझदारी यह सिद्धांत है कि आर्थिक एजेंटों (उपभोक्ताओं, उत्पादकों, श्रम) के पास सीमित तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता है, जो तीन मुख्य कारकों - संज्ञानात्मक क्षमता, समय की कमी और अपूर्ण जानकारी से प्रेरित है।

[4] आयात उदारीकरण और टैरिफ में कमी के साथ, भारत में बाजार प्रतिस्पर्धा तेजी से एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखी जा रही थी; पहले बड़े पूंजी-गहन उद्योगों द्वारा जो आयात प्रतिस्पर्धा से सीधे प्रभावित होते हैं और बाद में तेजी से अन्य सभी द्वारा।

प्रोत्साहित न करने की आवश्यकता होती है]। (ग) नव-शास्त्रीय विकास गतिशीलता: भौतिक पूंजी/निवेश का महत्व; मानव पूंजी (रोजगार कौशल), प्रौद्योगिकी (अनुसंधान एवं विकास)/ज्ञान (पोर्टल), दक्षता/उत्पादकता (टीएफपी)। (घ) शंपेटेरियन उद्यमिता, नई प्रौद्योगिकी (आर एंड डी) और विघटनकारी नवाचार को चलाने के लिए[5] के मुद्दे शामिल हैं।

ये विचार निजी उद्यमियों के लिए पूंजी जुटाने, उद्यमों का निर्माण करने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक अनुकूल नीति और संस्थागत वातावरण बनाने के लिए सरकार को प्रेरित करते हैं; और ऐसी नीतियां जो निजी क्षेत्र को आकर्षित करती हैं और उन्हें, जो वह सबसे अच्छा कर सकते हैं, के लिए सुविधा प्रदान करती हैं। भारतीय समाजवाद (1950-1980) द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और विनियमों के नियंत्रण मानसिकता और जटिल जाल को देखते हुए, पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रत्येक उत्पाद, प्राकृतिक संसाधन और कारक इनपुट को चिह्नित कर इन नियंत्रणों को हटाना है और उन्हें आधुनिक विनियमों के साथ बदलने का है, जो आर्थिक रूप से उचित है। व्यापार सुधार कार्य योजना ने नियामक अनुपालन को आसान बनाने के लिए व्यवस्थित रूप से 40,000 अनुपालनों को कम और / या सरल बनाया है। पहले किए गए सुधारों के आधार पर भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान सुधारों की एक श्रृंखला पर कार्य शुरू किया है और पूरा किया है जो 1990 के दशक के दौरान किए गए सुधारों से तुलना करता है। मूल विचार निजी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, नीति सृजित एकाधिकार को समाप्त करना, प्राकृतिक एकाधिकार, बाहरी कारकों और सूचना विषमताओं को विनियमित करने के लिए आधुनिक विनियमों का उपयोग करना और केवल सेक्टरों/उद्योगों/क्षेत्रों में सरकारी उत्पादन और सेवाओं को बनाए रखना (सीमित) है, जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इनमें माल और सेवा बाजारों और कारक बाजारों का उदारीकरण (जो पहले के सुधारों से अछूते थे), प्राकृतिक संसाधनों की खोज और खनन, निजी निर्माण और अवसंरचना का रखरखाव, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में सुधार, और डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था (परिशिष्ट 1 में विवरण) को बढ़ावा देना शामिल हैं।

यह तरीका एक साम्यवादी-समाजवादी, कमांड एंड कंट्रोल अर्थव्यवस्था और एक अति- पूंजीवाद के बीच एक मध्य मार्ग को दर्शाता है जिसमें किसी भी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप को संदेह के साथ देखा जाता है। स्वैच्छिक रूप से गठित समूहों सहित व्यक्तिगत पहल आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के चालक हैं, सरकार नहीं। सरकार क्रियान्वयनकर्ता और सुगमकर्ता हो सकती है और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए।

इस प्रकार सरकार ने कमियों को दूर करने और उन मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपने लिए अधिक जगह बनाई है जो निजी क्षेत्र करने में असमर्थ या अनिच्छुक है - सार्वजनिक माल का प्रावधान,

[5] एस एंड टी आधारित स्टार्टअप के वित्तपोषण की विधि को उत्पाद और प्रोटोटाइप विकास के कई चरणों को ध्यान में रखने और सफलता की उच्च संभावना वालों को निरंतर समर्थन प्रदान करने के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है।

वित्तपोषण और अवसंरचना का विनियमन। सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि परिवहन, ऊर्जा, संचार, औद्योगिक, शहरी और ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण किया जाए और अर्थव्यवस्था और नागरिकों को सबसे कुशल तरीके से प्रदान किया जाए। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश अवसंरचना को हिस्सों में बांट दिया गया है जो वर्चुअल सार्वजनिक वस्तुएं, अर्ध-सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं हैं, और बाजार प्रतिस्पर्धा के लिए उत्तरदायी हैं। प्रतिस्पर्धी आपूर्ति को अधिकतम करने के लिए बंटे गए हिस्सों को आवश्यक वित्तपोषण, निर्माण और सेवा प्रावधान भागों में और अलग कर दिया गया है। एक ओर, मोबाइल दूरसंचार अवसंरचना और सेवाओं और बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों को निजी क्षेत्र द्वारा वित्तपोषित और बनाया जा सकता है, लेकिन एक आधुनिक, पेशेवर नियामक और विनियमों द्वारा विनियमित करने की आवश्यकता है जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं और उचित उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हैं। दूसरी ओर, शुद्ध सार्वजनिक वस्तुओं जैसे ग्रामीण लिंक रोड और स्थानीय सड़कों को पूरी तरह से केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाना चाहिए, लेकिन निजी क्षेत्र द्वारा बनाया जा सकता है और स्थानीय सरकारों द्वारा रखरखाव किया जा सकता है। ऐसे सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रतिस्पर्धी बोली का व्यापक रूप से और प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। हालांकि, रेलवे लाइन और सिग्नलिंग प्रणाली, बिजली अंतरण और वितरण; या प्रमुख बंदरगाहों जैसी अर्ध-सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित और बड़े पैमाने पर बनाया और चलाया जाता है।

मध्य में राजमार्गों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जलमार्गों, बिजली और दूरसंचार से संबंधित निर्माण गतिविधियों, रखरखाव और सेवाओं और उपकरणों की एक श्रृंखला है जिसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के विभिन्न संयोजनों का उपयोग किया गया है। अवसंरचना सेवाएं जो निजी क्षेत्र द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क के एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी हैं और लाभदायक हैं, जैसे हवाई अड्डे, छोटे बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाहों और रेलवे स्टेशनों पर बर्थ की नीलामी की जाती है। जहां कम जनसंख्या घनत्व या दूरस्थता के कारण अवसंरचना लाभदायक नहीं है वहां सब्सिडी नीलामी का उपयोग किया जाता है।[6]

भारत सरकार ने डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं और सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र का नेतृत्व किया है। इसमें सभी नागरिकों/ निवासियों (आधार) के लिए विशिष्ट आईडी का विकास, भुगतान, डिजी लॉकर, इंडिया स्टैक और हेल्थ स्टैक के लिए एक यूनिवर्सल पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) शामिल है। इसने भारत सरकार (बाद में सभी राज्य सरकारों के लिए खोला गया) द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई-बाजार (जीईएम), राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईएनएएम) और डिजिटल वाणिज्य के लिए खुले नेटवर्क (ओएनडीसी)[7] जैसे इलेक्ट्रॉनिक बाजारों को बढ़ावा दिया है।

---

[6] विजेता को सबसे कम सब्सिडी की आवश्यकता होती है।

[7] शब्दावली में प्रत्येक कार्यक्रम, स्कीम और प्लेटफॉर्म का संक्षिप्त विवरण है।

मानव पूंजी विकास को कई सूचना/ज्ञान प्लेटफार्मों के माध्यम से बढ़ावा दिया गया है। स्किलिंग इंडिया, सशक्त, ई-पाठशाला, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, ऑनलाइन लैब, इंडिया एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म और किसान पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म का गठन किया गया था। चिकित्सा शिक्षा और सामान्य जन शिक्षा नीतियों को 21वीं सदी के भारत की मांगों के अनुसार संशोधित किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास इस नीति के साथ-साथ कौशल विकास और उद्यमिता नीति (2015) का एक अभिन्न अंग है। कौशल को पीएम कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान, शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीआई) और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के शुल्क-आधारित, निजी मांग संवेदनशील, मॉडल के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

विभिन्न समूहों के बीच नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। अटल नवाचार मिशन जमीनी स्तर पर छात्रों की कल्पना को बढ़ावा देकर नवाचार को प्रोत्साहित करने की अपनी तरह की पहली योजना है। इसमें अटल टिंकरिंग लैब, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया और ग्रैंड चैलेंज और मेंटर इंडिया जैसे कई घटक हैं। उद्यमिता और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने की योजनाओं में समृद्ध, स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड, स्टार्ट-अप नेतृत्व कार्यक्रम, नवाचार को बढ़ावा देने की योजना, ग्रामीण उद्योग और नवाचार (एस्पायर), स्टार्ट-अप के लिए क्रेडिट फंड (मुद्रा) और नवाचार को प्रेरित करने के लिए चैलेंज- चुनौती शामिल हैं।

पारंपरिक उद्यमियों और अनौपचारिक क्षेत्र (एमएसएमई) को कई पहलों के माध्यम से अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र में बदलने के लिए प्रेरित और समर्थित (उदयम पोर्टल) किया जा रहा है। इनमें प्रशिक्षण, क्रेडिट सिस्टम, गारंटी और खाता एग्रीगेटर (आरबीआई), तकनीकी सहायता और तकनीकी उन्नयन, कौशल (एमसीवाई), नवाचार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए अवसंरचना और कनेक्टिविटी (परिशिष्ट देखें) शामिल हैं।

ख.2. आर्थिक सुधार और परिणाम

1990 के दशक में किए गए सुधारों ने पांच से दस वर्षों के अंतराल के बाद प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को प्रभावित किया।[8] परिणामस्वरूप, 2004-13 के दौरान बढ़ती मुद्रास्फीति, अंतर्निहित दोहरे घाटे की समस्या और "हारे हुए दशक" के अंत में एक मिनी- बीओपी संकट के बावजूद, मौलिक सुधारों में रुकावट लगभग किसी की नजर में नहीं आई। भारतीय अर्थव्यवस्था ने असंशोधित उत्पाद और सेवा क्षेत्रों (कृषि,बिजली, शिक्षा), कारक बाजारों (श्रम, भूमि, पूंजी, प्रबंधन) और सरकारी व्यय, कर और सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित समस्याओं के साथ 2010 के मध्य में प्रवेश किया।

2012-13 के लघु भुगतान संतुलन संकट (मिनी-बीओपी) के बाद बैंक ऋणों से निपटने के लिए एक दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के माध्यम से अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों के लिए मैक्रो स्थिरता

[8] विरमानी (2006), विरमानी और हाशिम (2011)

बहाल करने के लिए शुरुआत में कुछ वर्ष लगा दिया गया था- लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) के लिए एक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) और स्थिर अप्रत्यक्ष कर राजस्व के लिए वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)[9]। 2019-20 के मध्य से व्यापक और गहन आर्थिक सुधार किए गए जो महामारी (2020 और 2021) के दौरान अधिक हुआ [10]। इनमें कई संस्थागत सुधार शामिल थे जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी (तेल, कोयला, खनिज, स्पेक्ट्रम),[11] प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (आधार, जाम, डीसीटी-किसान), पर्यावरण (बीएस6, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इलेक्ट्रिक वाहन), डिजिटल इंडिया (ई-जीओएम, जीईएम, यूपीआई)।

छूट और कटौती के उन्मूलन के साथ कॉर्पोरेट कर को घटाकर 25% कर दिया गया था,[12] सार्वजनिक क्षेत्र (कोयला, तेल, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, ड्रोन, मैप) द्वारा पहले एकाधिकार वाले उद्योगों में निजी और विदेशी प्रवेश की अनुमति दी गई थी। अर्थव्यवस्था में राज्य उद्यमों के हिस्से को कम करने के लिए एक रणनीतिक उद्योग नीति तैयार की गई थी। शिक्षा नीति (चिकित्सा शिक्षा सहित) को विनियमित निजी और विदेशी प्रवेश की अनुमति देने और व्यावसायिक शिक्षा को नियमित शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लिए उदार बनाया गया था।[13] श्रम संहिता और बिजली वितरण, भूमि और कृषि व्यापार नीति में सुधार के लिए प्रयास किए गए।[14] व्यापार करने में सुगमता (ईओडीबी) के लिए कानूनों, नियमों और विनियमन में सुधार के लिए निरंतर प्रयास जारी है।[15]

सुधारों के प्रभाव को देखते हुए महामारी और यूक्रेन युद्ध जैसे अंतराल और बाहरी झटकों से संभ्रमित है। हालांकि व्यापक चित्र सकारात्मक है। भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीसीजीडीपी) 2014 में विश्व औसत के 34% से बढ़कर 2022 में 041% हो गई है, इसी अवधि में इसकी विश्व रैंक 142 से बढ़कर 138 हो गई है। पूर्ण गरीबी इसी अवधि में 5.1% से घटकर 0.9% (वस्तु हस्तांतरण के लिए समायोजित) और 7.4% से 2.5% (असमायोजित) हो गई है (तालिका 1)।

---

[9] जीएसटी स्वतंत्रता के बाद के आर्थिक कानून का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन है। संवैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राज्यों के साथ कुछ समझौते करने पड़े। इन दुर्बलताओं को युक्तिकरण और सरलीकरण के माध्यम से हटाने की आवश्यकता है, जिसमें कुछ उत्पादों को छोड़कर बाकि सभी से उपकर को हटाना शामिल है।

[10] जो एक पुरानी कहावत की पुष्टि करता है - "संकट बहुत महत्वपूर्ण अवसर है जिसे बर्बाद नहीं करना चाहिए"।

[11] पिछले कुछ दशकों के वैश्विक अनुभव को देखते हुए, इन नीलामियों के डिजाइन में सुधार की गुंजाइश है।

[12] 2009 में एक नया प्रत्यक्ष कोड तैयार किया गया था। इसकी समीक्षा वित्त मंत्रालय की समिति द्वारा लगभग सात साल बाद की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय कर वातावरण में बदलाव के अनुसार इसे संशोधित करने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

[13] शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ प्रणालियों सहित डिजिटल प्रणालियों के अधिक से अधिक उपयोग की आवश्यकता है। सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हाइब्रिड सिस्टम में नवाचार की आवश्यकता है।

[14] चूंकि श्रम कानून समवर्ती सूची में हैं, इसलिए प्रत्येक राज्य द्वारा उनके कार्यान्वयन के लिए नियम तैयार करने के बाद (केवल कुछ ही बचे हैं) नए श्रम संहिताएं प्रभावी हो जाएंगे। हालांकि कृषि व्यापार कानूनों को वापस लेना पड़ा, स्वतंत्र अनुसंधान से पता चलता है कि इसी तरह के कानूनों ने किसानों की आय को अन्यत्र औसतन 38% बढ़ाया है।

[15] सरलीकृत किए जाने वाले कई कानून और नियम राज्यों के दायरे में आते हैं।

तालिका 1: विश्व और गरीबी दर के सापेक्ष भारत का प्रति व्यक्ति जीडीपी-पीपीपी

	2004	2014	2022
PcGdppp			
India/world	0.25	0.34	0.41
India Rank	148	142	128
(percentile)	21%	27%	30%
Poverty HCR (%)			(2020)
PPP$1.9/day	32.7	7.4	2.5
w food trnsfr	31.9	5.1	0.9
PPP$3.2/day	73.8	43.3	26.5
w food trnsfr	73.5	39.7	18.1
Source: WDI, WB & BBV(2021), IMF			

पीएलएफ से कृषि वर्ष 2017-18 (जुलाई 2017 से जून 2018) से कृषि वर्ष 2022-23 तक का लगातार डेटा भी उपलब्ध है। इससे पता चलता है कि श्रमिक-जनसंख्या अनुपात में 3.7% प्रति वर्ष (यूएस) और 3.3% प्रति वर्ष (सीडब्ल्यूएस) की वृद्धि हुई है। कृषि वर्ष 18 और कृषि वर्ष 23 के बीच आकस्मिक श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में प्रति वर्ष 4.1-4.2% की सबसे तेजी से वृद्धि हुई है और स्व-नियोजित की औसत आय 3-3.1% प्रति वर्ष हुई (तालिका 2)। महामारी के दौरान आकस्मिक श्रमिकों के वास्तविक मजदूरी में कम से कम गिरावट देखी गई, क्योंकि उनके पास कृषि में लौटने का विकल्प था जो आम तौर पर लॉकडाउन और महामारी से कम से कम प्रभावित था। स्व-नियोजित को महामारी के दौरान सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा लेकिन कृषि वर्ष 23 (तालिका 2) के दौरान स्थिति अच्छे से ठीक हो गया। कृषि वर्ष 23 में यह रिकवरी कृषि वर्ष 2022-23 के दौरान संपर्क सेवाओं और निर्माण की रिकवरी से जुड़ी है, जिसने आकस्मिक श्रमिकों की मांग और मजदूरी को भी बढ़ाया। विश्वकर्मा योजना (2023) सूक्ष्म उद्यमों की उत्पादकता और औसत आय को और बढ़ाने में मदद करेगा।

तालिका 2: रोजगार और वास्तविक मजदूरी

Agricultural year	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	Compound
							(simple avg)
Usual status (us)	**0.47**	**0.47**	**0.51**	**0.52**	**0.53**	**0.56**	**3.7**
Crnt Wkly St(CWS)	**0.44**	**0.44**	**0.47**	**0.48**	**0.48**	**0.52**	**3.3**
(gr rt)		0.3	5.3	1.8	1.6	7.0	3.2
Monthly Wage-ages 15-64							
Agricultural year	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22		
Real wages (rupees per month, deflated by CPI)							Ay22/Ay18
Casual Workers	**4713**	**4902**	**4967**	**5070**	**5316**	**5781**	**4.2**
(gr rt)		3.9	1.3	2.0	4.7	8.4	4.1
Salaried workers	**12924**	**12990**	**12992**	**12822**	**12809**	**13290**	**0.6**
(gr rt)		0.5	0.0	-1.3	-0.1	3.7	0.6
Self employed	**7304**	**7492**	**7287**	**6992**	**7413**	**8506**	**3.1**
(gr rt)		2.5	-2.8	-4.1	5.8	13.8	3.0
Nominal wages (Rupees per month)							
Casual Workers	6438	6895	7381	7980	8863	9834	**8.8**
Salaried workers	17653	18273	19307	20182	21359	22607	**5.1**
Self employed	9976	10539	10829	11006	12360	14470	**7.7**
CPI (2012)	**136.6**	**140.7**	**148.6**	**157.4**	**166.7**	**170.1**	**4.5**
Data: PLFS; Source for Nominal wage, Bhalla et al (2023); Real wage is calc by using monthly CPI (2012) averaged over agricultural year (july-june)							

डेटा: पीएलएफएसः असमायोजित मजदूरी के लिए स्रोत, भल्ला एट अल (2023); लेखक ने वास्तविक मजदूरी की गणना कृषि वर्ष (जुलाई जून) के औसतन से मासिक सीपीआई (2012) का उपयोग करके किया है।

वेतनभोगी श्रमिकों की औसत वास्तविक मजदूरी प्रति वर्ष 0.6% पर सबसे धीमी है जिसका तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था द्वारा आवश्यक नौकरी कौशल की पहचान करने और सृजित करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है (न कि सामान्य शिक्षा पर जो बहुत बढ़ गई है)।

ग. समाज कल्याण के लिए भारतीय दृष्टिकोण

स्तंभ 2: अंत्योदय और सशक्तिकरण

भारतीय विकास मॉडल का दूसरा व्यापक तत्व, अंत्योदय और सशक्तिकरण है। अंत्योदय का अर्थ समाज में सबसे वंचित लोगों की देखभाल करना है। सशक्तीकरण का अर्थ है समाज में सभी को अपनी प्रतिभा और/या आय सृजन क्षमता विकसित करने का अवसर प्रदान करना है।

प्रत्येक त्यौहार को मनाने और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/स्थानीय नेताओं के प्रत्येक के जन्मदिन मनाने का सरकार का प्रयास, देश के प्रत्येक नागरिक के दैनिक जीवन से जुड़ने का प्रयास है, और इस प्रकार उनके बीच एक अप्रत्यक्ष संबंध जुड़ता है। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

मोदी के नियमित, मासिक रेडियो वार्ता, “मन की बात” का भी लक्ष्य यही रहा है कि युवाओं और छात्रों सहित प्रत्येक भारतीय के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ें। यह प्रत्येक नागरिक के बीच आपसी संवेदना और समझ की नींव बना सकता है, चाहे उनके पृष्ठभूमि, पोशाक, भोजन की आदतें, आध्यात्मिक अभिविन्यास, सांस्कृतिक प्रतीक और जीवन शैली कितनी भी विविध क्यों न हो। सामाजिक करुणा इस पारस्परिक सहानुभूति और विचार-विनिमय का एक परिणाम है। दूसरी, उनकी प्राचीन विरासत की पहचान और अनुष्ठान के माध्यम से होने वाली सामाजिक सशक्तिकरण है।

श्री डी.डी. उपाध्याय ने इसे “इंटीग्रल ह्यूमनिज्म” नामक दर्शन में निरूपित किया, जिसके परिणामस्वरूप अंत्योदय नामक एक कल्याणकारी कार्यक्रम भी बना। डी बी थेगड़ी (1995), अपनी पुस्तक ‘थर्ड वे’ में एक समान दृष्टिकोण की बात की हैं। अंत्योदय सशक्तिकरण[16] “यूरोपीय कल्याण राज्य” का भारतीय प्रतियोगी है। भारतीय कल्याण राज्य समाज के सबसे निचले स्तर, सामाजिक-आर्थिक विकास और आय के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा, “सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी का चेहरा याद करो जो आपने देखा है और अपने आप से पूछो कि जो कदम आप सोच रहे हैं, क्या वह उसके किसी भी उपयोग का है”। यह एक ऐसी बात है जिस पर जनता, सभी समुदाय, सामाजिक-आर्थिक समूह और राजनीतिक दल भी पूरी तरह से सहमत है।[17] यह पहचान और समझ प्रधानमंत्री मोदी के सभी व्यवसायों और उपलब्धियों (खेल-औपचारिक/अनौपचारिक, कला/शिल्प, सामाज सेवा/कार्य, योग, आयुर्वेद, प्रौद्योगिकी विकास, स्टार्ट-अप नवाचार, शैक्षणिक उपलब्धि सहित) को महत्व देने में परिलक्षित है। सबसे स्थानीय से लेकर उच्चतम वैश्विक स्तर तक ले जाने वाली आकांक्षाओं को प्रोत्साहित और समर्थित किया जाना चाहिए।

समाज कल्याण के लिए भारतीय दृष्टिकोण बहुआयामी है, जिसमें सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्राप्तकर्ताओं को प्रत्यक्ष अंतरण और अप्रत्यक्ष सब्सिडी, नकद हस्तांतरण (जैसे किसानों को) और वस्तु और सेवाओं के मुफ्त या कम बाजार मूल्य प्रावधान (जैसे छात्रवृत्ति) और "बुनियादी जरूरतों" की एक व्यापक श्रृंखला के रूप में वस्तुगत अंतरण शामिल हैं[18]। विकास अर्थशास्त्रियों ने तब से परिणामों के संदर्भ में, इनमें से कुछ भारतीय कल्याण और विकास प्रथाओं को औपचारिक रूप देकर परिमाण निर्धारित किया है जिसे बहु-आयामी गरीबी संकेतक कहा जाता है।

---

[16] श्री दीन दयाल उपाध्याय ने इसे एक दर्शन के रूप में तैयार किया जिसे “अभिन्न मानववाद” कहा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अंत्योदय [उपाध्याय (2021)] नामक एक कल्याणकारी कार्यक्रम भी शुरु हुआ। सशक्तिकरण की भारतीय अवधारणा के लिए। विरमानी (2002) भी देखें।

[17] जॉन रॉल्स ने इनमें से कुछ विचारों को औपचारिक रूप दिया, और डैनियल चांड्लर ने विकसित देशों के समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप कुछ विचारों को फिर से तैयार किया है। भारत ने हमेशा महात्मा गांधी की अवधारणाओं को अपनी विकास नीति में शामिल किया है, हालांकि उन्हें एक मिश्रित (समाजवादी-पूंजीवादी) अर्थव्यवस्था मॉडल के संदर्भ में औपचारिक रूप नहीं दिया गया था, जिसका भारत ने 1990 तक पालन किया था।

[18] *राजनीतिक बोलचाल में, इन्हें कभी-कभी "रोटी, कपड़ा, मकान" कहा जाता था।*

सबसे गरीब, दिव्यांग, वृद्ध और व्यक्तिगत त्रासदी या दुर्भाग्य का सामना करने वालों का कल्याण, भारत के सांस्कृतिक इतिहास का एक हिस्सा रहा है, जिसे आधुनिक दुनिया के अनुकूल बनाया गया है और एक आधुनिक संकल्पना प्रदान की है। लक्षित, चयनात्मक सुरक्षा जाल प्राकृतिक आपदाओं और मैक्रो झटके से प्रभावित लोगों के लिए है जो उनके नियंत्रण से परे है और सबसे सचेत परिवारों की भी क्षमता से परे चिकित्सा त्रासदियों के लिए हैं! महामारी के दौरान भारतीय आबादी के 2/3 हिस्से (यानी 900 मिलियन से अधिक लोगों) को मुफ्त भोजन (मुख्य रूप से अनाज) का प्रावधान करना इस तरीके का एक बहुत ही सफल उदाहरण है।

शोध से पता चला कि गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के परिवारों में आय अर्जक की भयावह बीमारी ऐसे परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) धकेलने का एक प्रमुख कारक था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा योजना, जिसमें 100 मिलियन गरीब और कमजोर परिवारों को शामिल किया गया है, इस समस्या का समाधान करती है। पीएम जेएवाई लगभग 550 मिलियन लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 500,000 रुपये का कवर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एक सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है, जो आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांगता के मामले में 200,000 रुपये प्रदान करती है और यह अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के परिवारों के लिए अमूल्य है।

कार्यक्रमों और परियोजनाओं की अवधारणाएं और प्राथमिकता समय के साथ बदल गई है और विकसित हुई है और मौजूदा योजनाओं को पुनःसंरचित, पुनः प्रारंभ कर बहुत अधिक उत्साह और कम समय सीमा के साथ इन्हें जारी रखा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना को 2015 में एसजीएसवाई में एकीकृत किया गया था। मिड-डे मील योजना को पीएम-पोषण के रूप में फिर से शुरू किया गया, जो समग्र पोषण के लिए एक व्यापक योजना है। सबसे सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक, स्वच्छ भारत मिशन ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी नागरिकों के घर में शौचालय हो और सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शौचालय सुविधाओं सहित सार्वजनिक शौचालयों तक पहुंच हो। जल जीवन मिशन और हर घर जल योजना देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ नल का जल उपलब्ध कराने की कगार पर हैं। पीएम आवास योजना ने हर परिवार को पक्का घर बनाने और उसमें रहने का अवसर प्रदान किया है। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को हर गांव में बिजली प्रदान करने के लिए उपयुक्त पीएम सौभाग्या, सहज बिजली योजना द्वारा सक्रिय और पूरक किया गया है।

नए क्षेत्रों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उदाहरण के लिए, वित्तीय समावेशन संकेतक संयुक्त राष्ट्र एसडीजी लक्ष्यों का भाग नहीं हैं, जबकि भारत के समावेशन दृष्टिकोण का भाग हैं। जन धन योजना के अलावा, पहले छूट गए लोगों को अधिकतम लाभान्वित करने के लिए जेएएम ट्रिनिटी की शुरुआत की गई थी। उज्ज्वला योजना उन घरों में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन लेकर आई है जो पहले पूरी तरह से अत्यधिक प्रदूषणकारी लकड़ी के स्टोव या केरोसिन पर निर्भर थे। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम

ज्योति योजना और भारत लैंप योजना, पीएम सौभाग्या: सहज बिजली हर घर योजना और उन्नत ज्योति योजना द्वारा हर घर में बिजली कनेक्शन और ऊर्जा कुशल एलईडी प्रदान करने के लिए सक्रिय और पूरक थे। इस प्रकार अवसंरचना विकास का दोहरा लक्ष्य है; प्रतिस्पर्धा, उत्पादकता और विकास में सुधार करना और नागरिकों को अधिकतम संभाव्य तरीके से सशक्त करना।

विकास का एक संबंधित क्षेत्र सशक्तिकरण की अवधारणा (जेडीवाई, जेएएम, पीएमबीएसवाई) का विकास, सुदृढ़ीकरण और परिष्करण, और "अवसर की समानता" का कार्यान्वयन रहा है। यह भारत के लोगों के बीच अविश्वसनीय विविधता से प्रभावित हुआ है- पृष्ठभूमि (समूह) की विविधता, और व्यक्तिगत आकांक्षाएं और लक्ष्य। यह यूरोपीय राष्ट्र राज्यों और कई अफ्रीकी और एशियाई देशों की एकरूपता के विपरीत है। भारत की विविधता निरंतर बनी हुई है, जो हजारों साल पहले वैदिक काल से चली आ रही सांस्कृतिक-सभ्यतागत एकता की सहस्राब्दियों की विरासत है। लोगों के विभिन्न समूहों और भारत के विभिन्न भागों के लिए अलग-अलग अवसर, भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति के साथ-साथ विभाजन और अपनिर्वचनों की इसकी विरासत से है। इससे प्राचीन दर्शन, संस्कृति और इतिहास से अवगत आधुनिक विचारकों के बीच एक दृढ़ विश्वास पैदा होता है कि आधुनिक भारतीय समाज (सरकार, गैर सरकारी संगठनों) को हर समूह (महिलाओं, युवाओं, गरीब, किसानों) में लोगों को सशक्त बनाना चाहिए, और उन्हें अपने व्यक्तिगत हितों/महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अवसर देना चाहिए। लेकिन यह भी, विश्वास है कि एक बार समान अवसर प्रदान किए जाने पर व्यक्तिगत प्रेरणा और व्यक्तिगत मेहनत सफलता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। सशक्तिकरण, समाज कल्याण और "अवसर की समानता" की भारतीय अवधारणा में एक बड़ा परस्पर व्यापन है। सामान्य अखिल भारतीय योजनाएं और वंचित क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक समूहों के लिए विशेष योजनाएं हैं। तथापि, यदि समय-समय पर समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन न किया जाए तो इस प्रकार के "परिपूर्णता दृष्टिकोण" ओवरलैप और अपव्यय का कारण बन सकता है।

वंचित क्षेत्रों (जैसे, ग्रामीण) और समूहों (जैसे, महिलाओं) के समावेशन और सशक्तिकरण के एजेंडे को परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए), स्वमित्र योजना, सांझी योजना ग्रामीण विकास के लिए है, पीएम जनधन विकास योजना बहु क्षेत्रीय विकास के लिए है, जबकि राष्ट्रीय कैरियर सेवा और गरीब कल्याण रोजगार अभियान, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कल्याण रोजगार योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनाएं गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के नौकरी कौशल में अंतर को पाटने का प्रयास करती हैं।[19]

[19] बड़ी संख्या में योजनाओं (सीएस और सीएसएस) को देखते हुए, कम से अधिक प्रभावी योजनाओं के लिए धन के पुन: आवंटन को निर्धारित करने के लिए एक लाभ-लागत विश्लेषण की आवश्यकता है।

ग.2 निष्पादन और परिणाम

एनएफएचएस डेटा (तालिका 3) के आधार पर 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी के संकेतकों में सर्वांगीण सुधार इन योजनाओं की सफलता का एक संकेत है। इन संकेतकों में सबसे अधिक सुधार निर्धनतम राज्यों और उन संकेतकों में हुआ है जो सबसे खराब थे। एमडीपी का सकल सूचकांक घटकर ~15% हो गया है जो $3.2/दिन/व्यक्ति गरीबी रेखा (तालिका 1) पर आधारित 18% गरीबी दर से कम है।

तालिका 3: बहुआयामी गरीबी के संकेतक (नीति 2023)

Headcount Ratio: % of total population deprived in each indicator				
Dimension	**Indicator**	**NFHS-4 (2015-16)**	**NFHS-5 (2019-20)**	**Change (5 yrs)**
Health	Nutrition	37.6%	31.5%	-6.1%
	Child & Adolescent Mortality	2.7%	2.1%	-0.6%
	Maternal Health	22.6%	19.2%	-3.4%
Education	Years of Schooling	13.9%	11.4%	-2.5%
	School Attendance	6.4%	5.3%	-1.1%
Standard of Living	Cooking Fuel	58.5%	43.9%	-14.6%
	Sanitation	51.9%	30.1%	-21.8%
	Drinking Water	10.9%	7.3%	-3.6%
	Electricity	12.2%	3.3%	-8.9%
	Housing	45.6%	41.4%	-4.3%
	Assets	14.0%	10.2%	-3.8%
	Bank Account	9.7%	3.7%	-6.0%

"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ: मिशन शक्ति, सामाजिक आंदोलन, भारत आयुष्मान, वन नेशन वन हेल्पलाइन और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता सेवा (ईआरएसएस), सुरक्षित शहर परियोजना और महिला हेल्प डेस्क को मजबूत बनाने और महिला पुलिस अधिकारियों की भर्ती के माध्यम से महिलाओं के प्रति असमानता को ठीक करने और महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान प्रमाण पत्र, पीएम मातृत्व वंदना योजना जैसी कई योजनाएं, घर निर्माण, निजी और सार्वजनिक शौचालय, स्वच्छ पेयजल, और एलपीजी जैसी सामान्य योजनाओं के पूरक हैं, जो महिलाओं के जीवन और काम की नीरसता को दूर करने में मदद करती हैं। पोषण अभियान, सीएमपीओ जैसे बच्चों के कार्यक्रम भी महिलाओं पर असमान बोझ को हल्का करते हैं। महिलाओं पर

समान ध्यान सुनिश्चित करने के लिए पीएमजीदिशा, एनआरएलएम और उद्यमिता कार्यक्रमों जैसे कई ग्रामीण कार्यक्रमों में सुधार किया जा रहा है।

महिला कार्यबल भागीदारी दर (एफडब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 19.7 से बढ़कर 2022-23 में 27.6 हो गई है (चित्र 1)। ग्रामीण क्षेत्रों में एफडब्ल्यूपीआर में वृद्धि ~ 23% अंक थी, और शहरी क्षेत्रों में ~ 5% अंक थी। कृषि में महिला श्रमिकों की वृद्धि 70% थी, इसमें से आधे से अधिक वृद्धि पुरुषों द्वारा रिक्त की गई नौकरियों में थी। कामकाजी आबादी के प्रतिशत के रूप में महिला श्रमिकों की संख्या सेवाओं में 9.5% से बढ़कर 12.5% और विनिर्माण क्षेत्र में 2.75% से बढ़कर 4% हो गई।[20]

चित्र 1: महिला सशक्तिकरण: रोजगार

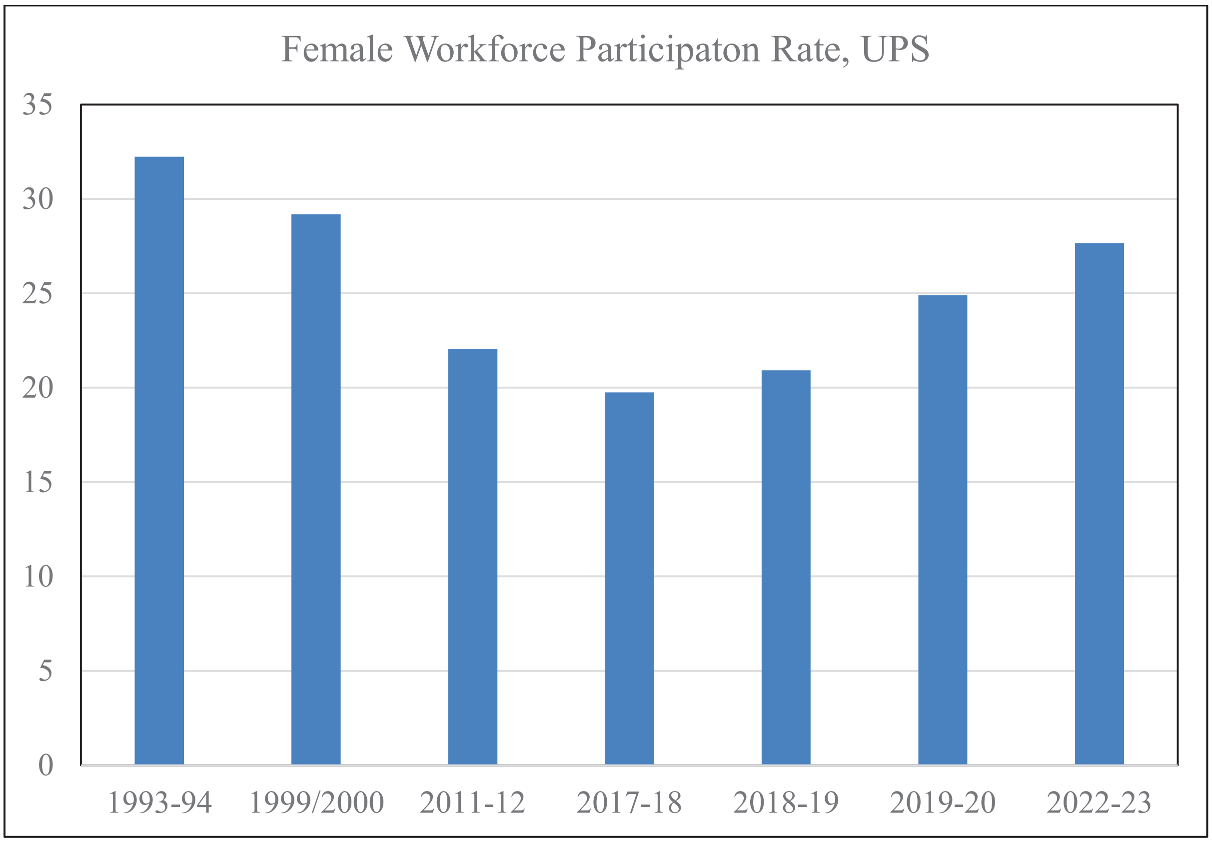

स्रोत: ईयूएस और पीएलएफएस का उपयोग करके गोल्डर और अग्रवाल (2023) द्वारा तैयार किया गया। यूपीएस=सामान्य मुख्य स्थिति

यदि प्राइम एज वर्कर्स (25-64) और कॉलेज शिक्षित श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो प्रदर्शन और भी बेहतर है। इस आयु में महिला श्रम बल भागीदारी दर में एवाई 2017-18 और निर्धारण वर्ष 2022-23 के बीच 50% की वृद्धि हुई है (तालिका 4)। इसी प्रकार, कॉलेज शिक्षित महिलाओं और पुरुषों के

[20] स्रोत: गोल्डर और अग्रवाल (2023)

बीच वेतन अंतर अविवाहित महिलाओं के लिए 3% और विवाहित महिलाओं के लिए 16% है (तालिका 5)।

तालिका 4: महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (एलएफपीआर) – मुख्य आयु

Usual Status Labour Force Participation India-Levels & Gender Gap				
	2011	2017	2019	2022
Women in labour Force (%)				
Ages 25-64	37.5	29.6	37.5	45.6
Men in labour Force (%)				
Ages 25-64	95.8	94	94.4	95.3
*Gap - Labor force Participation (%) **				
Ages 25-64	60.9	68.5	60.3	52.2
Source: NSS PLFS data various years; World Bank financed study,				
Authors: Surjit S Bhalla, Tirtha Das, Karan Bhasin, Abhinav Motheram,				
*Notes: * Gender Gaps are defined as 100* (Male value - Female value)/Male Value;*				
Data for Usual status definition of employment i.e. worked at least 30 days in year.				

तालिका 5: कॉलेज शिक्षितों के बीच लिंग वेतन अंतर: संयुक्त राज्य अमेरिका के सापेक्ष भारत

Gender Wage Gap in 2022 (in % of male wage)		
	India	USA
All workers	30	17
College educated		
Unmarried (single, widowed,separated)	3	6
Married	16	20
Source: Surjit Bhalla calculation based on PLFS		

घ. समष्टि आर्थिक प्रबंधन के लिए भारतीय दृष्टिकोण

स्तंभ 3: समग्र दृष्टिकोण: व्यावहारिकता

भारत हमारे आध्यात्मिक दर्शन और सभ्यतागत संस्कृति पर आधारित एक समग्र दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। मानवता की एकता वसुदैव कुटुम्बकम् वाक्यांश में परिलक्षित होती है।[21] यद्यपि भौतिक ब्रह्मांड से निपटने में तर्क और अनुभववाद का एक केंद्रीय स्थान है, लेकिन एक गहरा अंतर्ज्ञान है जो केवल गहन चिंतन या ध्यान से उत्पन्न हो सकता है। यह अत्यधिक जटिल और परस्पर जुड़े मुद्दों के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण दर्शाता है।

'हरित अर्थव्यवस्था' के प्रति भारत का समग्र दृष्टिकोण इसका एक उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की शुरुआत, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण (लाइफ) के लिए जीवन शैली कार्यक्रम पर जोर देना, जिसमें जल उत्पादक श्रीअन्न द्वारा जल सघन अनाज का प्रतिस्थापन और स्वास्थ्यवर्द्धक सब्जियों और फलों द्वारा कार्बन गहन मांस उत्पादों का प्रतिस्थापन शामिल है। हरित अर्थव्यवस्था के लिए समग्र दृष्टिकोण के अन्य तत्वों में मरम्मत योग्य और/या पुनर्चक्रण योग्य घरेलू उपकरणों द्वारा फेंकने वाले उत्पाद शामिल हैं।

समष्टि आर्थिक प्रबंधन समग्र दृष्टिकोण का एक और उदाहरण है। इसका एक प्रमुख तत्व प्रत्येक देश के सभी सिद्धांतों, अनुभवजन्य साक्ष्य और अनुभव के लिए प्रयोगसिद्ध है, किन्तु हमारी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकता में स्वयं को दृढ़ता से जोड़े रखती है। सरकार सहज रूप से सिद्धांत और विचारधारा पर अनुभव और साक्ष्य को प्राथमिकता देती है। साक्ष्य विश्वसनीय, भरोसेमंद, वार्ताकारों के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। यह पता लगाना कि कौन सी नीतियां काम करती हैं और कौन सी नहीं, लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन सी अधिक प्रभावी/कुशल है, सुधार के लिए लगभग एक आवश्यक शर्त है। परिणाम व्यावहारिक नीति निर्माण है जो सिद्धांत, औपचारिक और उपाख्यानात्मक साक्ष्य और नीतियों में सुधार के लिए फीडबैक लूप के साथ नीति निर्माण में एक पुनरावृत्त दृष्टिकोण को भारांक प्रदान करता है। पीएम साक्ष्य के स्रोत के बारे में बहुत उदार हैं; किन्तु विचारधारा या आत्म-सेवारत सिद्धांत से उत्पन्न चयन पूर्वाग्रह के प्रति सतर्क भी हैं।[22]

समग्र दृष्टिकोण सरकार की भूमिका की परिभाषा में भी परिलक्षित होता है। बुनियादी ढांचे के विकेंद्रीकरण और इसके वित्तपोषण के रूप में, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक निजी भागीदारी-

---

[21] सभी जीवित प्राणियों की एकता पशु विशेषताओं और प्रकृति के प्रति श्रद्धा के साथ वस्तुओं की पूजा में परिलक्षित होती है। दृश्य ब्रह्मांड और अदृश्य वास्तविकता की अंतर्निहित एकता आत्मा और परमात्मा की अवधारणा में परिलक्षित होती है।

[22] नए वैश्विक अवसरों के संदर्भ में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए समग्र मिश्रित आर्थिक विश्लेषण, कर व्यवसायियों, सीए और राजस्व संग्रहकर्ताओं के अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्य के आधार पर केंद्र सरकार के सभी करों का व्यापक कर सुधार आवश्यक है।

को प्रभावशीलता (पीपीपी), दक्षता, न्यूनतम लागत और अधिकतम गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न बंडलों के असाइनमेंट की सुविधा प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण को व्यवहार्य, उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए अभूतपूर्व उत्साह के साथ अपनाया जाता है।

अनुभव आधारित व्यावहारिकता राजकोषीय रूढ़िवाद की ओर भी ले जाती है; घरेलू वित्त और व्यावसायिक निवेश के रूढ़िवादी सिद्धांतों को सरकारी वित्त पर लागू किया जाता है, अनुत्पादक व्यय को कम करता है और उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश के लिए उधार लिया जाता है जिसमें लाभांश उधार लेने की लागत से अधिक होती है। राजकोषीय गुणकों पर अनुभवजन्य साक्ष्य को राजकोषीय नीति में उचित भारांक दिया जाता है। अनुभवजन्य अनुमानों से पता चलता है कि भारत में सरकारी पूंजीगत व्यय गुणक राजस्व व्यय गुणक का 2.5 गुना है, जिससे भारत सरकार के पिछले तीन बजटों में से प्रत्येक में पूंजीगत व्यय आवंटन में अंतरराष्ट्रीय पारंपरिक ज्ञान और आंतरिक दबावों के बावजूद, वार्षिक 33% की वृद्धि हुई है। भारत सरकार ने वर्ष 2020 में बड़े राजकोष प्रोत्साहित नहीं किया, किन्तु सावधानीपूर्वक उन लोगों को जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी उनके लिए व्यय और वित्तीय सहायता को लक्षित किया। लॉकडाउन और महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं को देखते हुए, इसने चरणबद्ध दृष्टिकोण भी अपनाया; नई सूचना के लिए नए उपायों का परिचय देना जो समस्या की प्रकृति और आयाम को स्पष्ट करता है (उदाहरण के लिए, कौन से क्षेत्र और खंड सबसे अधिक प्रभावित थे, और क्या समस्या मांग या आपूर्ति पक्ष पर थी)।

एक समग्र दृष्टिकोण यह भी तय करता है कि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के साथ मौद्रिक आग्रह को सरल कर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जो जीडीपी वृद्धि के महत्व के साथ उचित रूप से संतुलित होता है, आपूर्ति ढांचे के साथ भारत के अनुभव को देखते हुए, जो ऐतिहासिक रूप से मानसून की विफलता से उत्पन्न होता है। क्रेडिट नीति का उपयोग राजकोषीय और मौद्रिक नीति की सहायता के लिए भी किया जाता है, जो खंडित (अनौपचारिक) और लापता वित्तीय बाजारों के साथ भारतीय अनुभव पर आधारित है। महामारी, अपनी व्यापक और विविध अनिश्चितताओं के साथ, समग्र-व्यावहारिक दृष्टिकोण के मूल्य का प्रदर्शन करती है; विभिन्न क्षेत्रों तथा भौगोलिक क्षेत्रों में सकारात्मक और नकारात्मक मांग-आपूर्ति असंतुलन को देखते हुए क्रेडिट उपायों को सावधानीपूर्वक लक्षित किया गया था। मौद्रिक उपायों को भारत सरकार द्वारा ऋण गारंटी जैसे राजकोषीय उपायों के साथ भी समन्वित किया गया था। फीडबैक लूप के साथ नीति के लिए पुनरावृत्त दृष्टिकोण की सफलता, इस प्रकार अभूतपूर्व महामारी के जोखिम के तहत राजकोषीय, मौद्रिक और क्रेडिट नीति के प्रबंधन में प्रदर्शित की गई थी।

मैक्रोइकॉनॉमिक्स, माइक्रोइकॉनॉमिक्स के विपरीत, सभी प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक चर पर कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत या स्पष्ट अनुभवजन्य साक्ष्य के साथ अत्यंत विषम है। ज्यादातर मामलों में, सिद्धांतों को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में किए गए अनुसंधान के आधार पर तैयार किया गया है, किन्तु उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) और अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के लिए उनकी

प्रयोज्यता को और अधिक मान्य किया जाना है। अनुभवजन्य साक्ष्य काफी हद तक एई से है, क्योंकि ईएमई और एलडीसी में अनुसंधान की गुणवत्ता दुर्लभ उपलब्धता और डेटा की खराब गुणवत्ता से विवश है। इसलिए एई और ईएमई में विभिन्न नीतियों की प्रभावकारिता के बीच अंतर हैं। परिणामस्वरूप, अनुभवजन्य साक्ष्य आर्थिक विकास के चरण, समय, स्थान और जोखिम प्रकृति से भिन्न हो सकते हैं। ऐसी कोई नीतियां नहीं हैं जो विकास को तेज करने के लिए सार्वभौमिक रूप से काम करती हैं, केवल नीतियों का एक सेट है जिसे संभाव्य रूप से अच्छे/सकारात्मक, खराब/नकारात्मक और तटस्थ में रखा जा सकता है।

घ.2 मैक्रो-प्रबंधन: मुद्रास्फीति

इस समग्र-व्यावहारिक समष्टि आर्थिक प्रबंधन का परिणाम 2014-15 की दूसरी तिमाही से सीपीआई मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट थी (रेखाचित्र 2)।

औसत सीपीआई 10 तिमाहियों में 9.4% से वित्त वर्ष 2015 की पहली तिमाही में घटकर बाद की 10 तिमाहियों में 5.1% रह गयी (सारणी 6)। विश्वव्यापी महामारी के कारण आपूर्ति में व्यवधान के बावजूद, मुद्रास्फीति का औसत 4.9% से भी कम था। समग्र मैक्रो-प्रबंधन का प्रभाव 2013-14 से बीओपी असंतुलन में गिरावट और बैंकिंग प्रणाली के सकल और शुद्ध एनपीए में भी परिलक्षित हुआ है। कॉरपोरेट क्षेत्र की बैलेंस शीट भी मजबूत हुई और एफडीआई को पूर्वव्यापी कर भय से उबारा गया।

चित्र 2: मुद्रास्फीति सीपीआई (नई श्रृंखला)

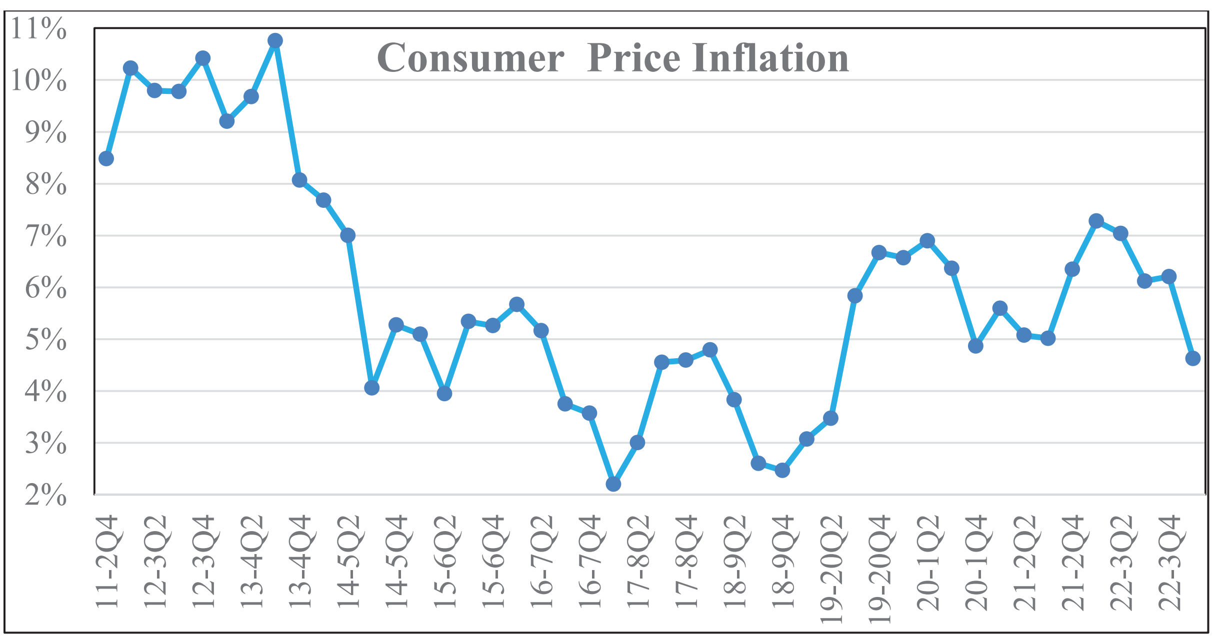

स्रोत: लेखक संकलन।

तालिका 6: तिमाही सीपीआई मुद्रास्फीति

औसत सीपीआई मुद्रास्फीति (%)	
तिमाहियां	**जीआर दर**
2011-2q4 to 2014-5q1	9.4
2014-5q2 to 2016-7q3	5.1
2014-5q2 to 2023-4q1	4.9

स्रोत: लेखक गणना।

कई विकास/वृद्धि आख्यान भी हैं जो अंतर्ज्ञान को तीव्र करती हैं और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। आर्थिक विकास और अल्पकालिक मैक्रो-प्रबंधन विशेष रूप से ईएमई और एलडीसी में, के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है। इसके लिए सैद्धांतिक कार्य और अनुभवजन्य साक्ष्य के समृद्धि की समझ की आवश्यकता होती है, और इसे मैक्रो-आर्थिक प्रबंधन और अंतर्ज्ञान के व्यावहारिक अनुभव के साथ संयोजित किया जाता है। जटिल मैक्रो-इकोनॉमिक लिंकेज, जैसे अप्रत्यक्ष करों (आयात शुल्क, निर्यात शुल्क और वैट / जीएसटी), और प्रत्यक्ष कर कोड की संरचना से उत्पन्न होते हैं, सतह के नीचे कार्य करते हैं, और स्पष्ट/दृश्यमान नहीं होते हैं, इस प्रकार सामान्य से अधिक व्यापक और गहन समग्र

परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है।[23] इसलिए उन्हें कम प्राथमिकता प्राप्त हो सकती है, जब तक कि उनमें से प्रत्येक के अंतर्निहित विशिष्ट सिद्धांतों और अनुभवजन्य साक्ष्य का अध्ययन, एकीकृत और लागू नहीं किया जाता है।

घ.3 निवेश और उत्पादकता

हालांकि विकास पर नीतिगत सुधारों का प्रभाव जे वक्र प्रभावों [विरमानी और हाशिम (2011) और विरमानी (2020)] ने चकित किया है, निवेश और उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव के कुछ संकेतों का पता लगाया जा सकता है। विरमानी (2018) ने दर्शाया कि निवेश दर में गिरावट, अपने चरम से पूरी तरह से आवास, वाणिज्यिक अचल संपत्ति और संरचनाओं में घरेलू निवेश में गिरावट के कारण है। यदि स्थिर कीमतों का विश्लेषण किया जाए तो गिरावट काफी हद तक विपरीत होगी। आरबीआई से संशोधित और विस्तारित निरंतर मूल्य श्रृंखला हमें इस मुद्दे पर पुनः विचार करने की अनुमति देती है। वर्ष 2022-23 में वास्तविक निवेश दर (जीएफसीएफ/जीडीपी) 34% है, जो इसके 34.3% के शीर्ष से मामूली कम है जो 2011-12 में लगभग पुनः शीर्ष पर लौटा है (रेखाचित्र 3)। हालांकि, वि.व.15 से वि.व.23 के दौरान औसत इन्वेस्टमेंट दर 31.8% है, वि.व.2005 से वि.व.2014 के दौरान 31% औसत से 0.8% पॉइंट अधिक है। वि.व.2022 तक उपलब्ध परिसंपत्तियों और संस्थागत क्षेत्र द्वारा सकल स्थायी पूंजी

[23] उद्योगों और आर्थिक एजेंटों के विभिन्न समूहों में इन प्रभावों की माप और समझ के लिए सैद्धांतिक और अनुभवजन्य मॉडलिंग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, इसके लिए विशिष्ट देश की मैक्रो अर्थव्यवस्था के ज्ञान और अंतर्ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। एग्रो वेबसाइट पर कागजात की एक श्रृंखला है।

निर्माण पर डेटा पुष्टि करता है कि शीर्ष से अधिकांश गिरावट आवास आदि में घरेलू प्रत्यक्ष निवेश के कारण थी, जो 2013-14 की तुलना में 2015-16 से 2017-18 के दौरान वास्तविक जीडीपी के 1.4% अंक कम थी (तालिका 7)। अन्य सभी निश्चित निवेश 2011-12 से अपट्रेंड पर हैं और 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद के 22.6% के पिछले शीर्ष की तुलना में 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का 24.6% था। बुनियादी ढांचे के घरेलू निवेश में गिरावट की प्रवृत्ति भौतिक परिसंपत्तियों के घरेलू बचत में गिरावट की प्रवृत्ति से परिलक्षित होती है, जिसमें सकल घरेलू और शुद्ध बचत में पूरी गिरावट भौतिक परिसंपत्तियों में बचत द्वारा बताई गई है (तालिका 8)।[24] तालिका 8 से यह भी पता चलता है कि हालांकि कुल कॉर्पोरेट निवेश में बहुत उतार-चढ़ाव आया है, 2021-22 में निजी कॉर्पोरेट निवेश 2012-13 के समान ही है, और 2011-12 से 2013-14 के औसत से अधिक है।

चित्र 3: 2011-12 के स्थिर मूल्यों में सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ)

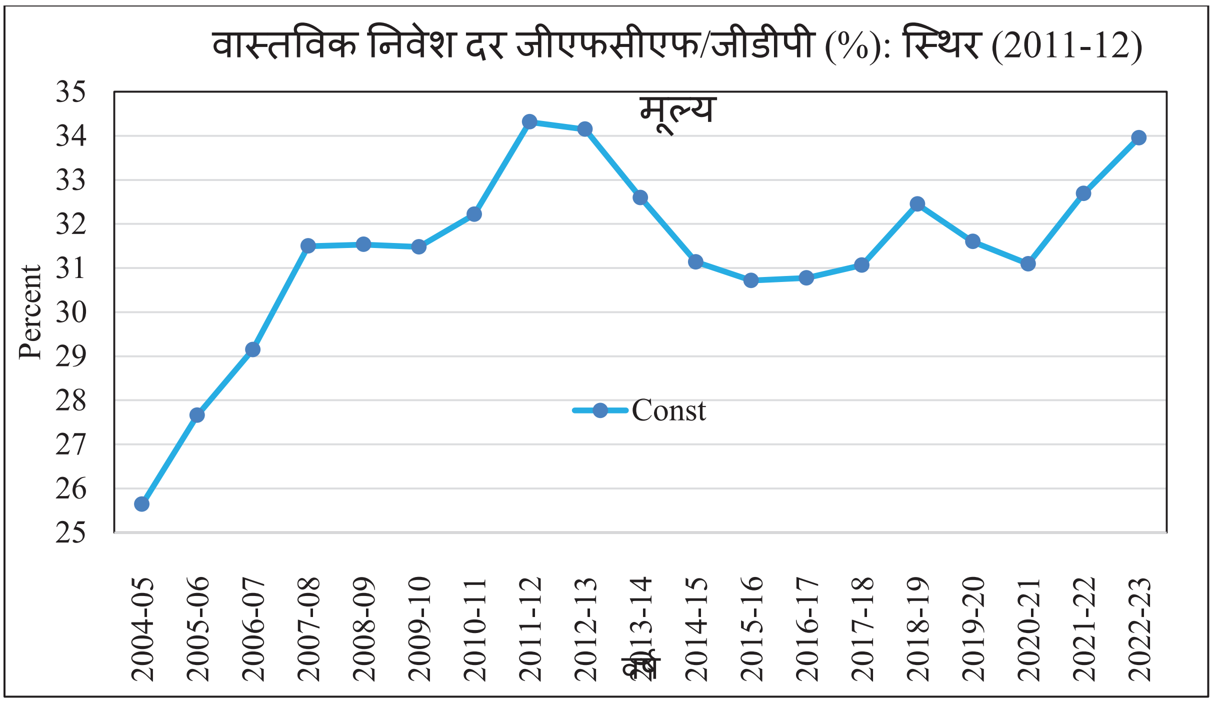

स्रोत: लेखक संकलन

[24] यह गिरावट रियल एस्टेट में कालेधन के लेन-देन के विरुद्ध की गई कार्रवाइयों और रेरा के प्रख्यापन के जरिए उद्योग को स्वच्छ बनाने के प्रयासों से जुड़ी है। परिणामस्वरूप, मुंबई और दिल्ली के प्रमुख महानगरों में वास्तविक मूल्य वृद्धि पूरी तरह से बंद हो गई, जैसा कि आवास मूल्य सूचकांक से देखा गया है। वास्तविक कीमतों ने हाल ही में बढ़ना शुरू कर दिया है, जो नई, क्लीनर प्रणाली के तहत मांग में क्रमिक पिकअप का संकेत देता है।

तालिका 7: 2011-12 में लगातार मूल्यों पर निवेश दर (जीएफसीएफ/जीडीपी) (%)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
GFCF	34.3	34.1	32.6	31.1	30.7	30.8	31.1	32.4	31.6	31.1	32.7	34.0
HH Houses, building	12.8	11.5	11.1	10.3	7.7	7.7	7.7	8.1	7.3	7.9	8.1	
GFCF-HHhsbldg	21.5	22.6	21.5	20.8	23.0	23.1	23.4	24.3	24.3	23.2	24.6	
Private corporations	32.7	36.1	38.8	37.1	41.3	38.9	36.4	35.2	37.9	37.4	36.1	
Corporate (pvt & public)	15.1	16.0	16.3	15.1	16.7	15.4	14.7	15.3	15.3	14.7	15.0	
Note: GFCF for 2019-20 to 2021-22 has been revised, but institutional detail is unavailable.												
In this table we have attributed the entire revision to HH investment which is mostly a residual												
HH = Household												

तालिका 8: वर्तमान मूल्यों में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घरेलू बचत

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Gross HH Savings	27.0	25.8	23.5	22.6	20.8	21.2	23.7	24.4	23.0	26.3	23.1
Net HH Savings	23.6	22.5	20.3	19.6	18.0	18.1	19.3	20.3	19.1	22.4	19.7
Net financial saving	7.4	7.4	7.4	7.1	8.1	7.4	7.6	7.9	7.7	11.5	7.6
Saving in physical assets	15.9	14.7	12.6	12.1	9.6	10.4	11.4	12.2	11.2	10.7	11.8
(direct investment)											
Note: Finances for Gross Capital Formation are only produced at current prices											

पिछले तीन बजटों में से प्रत्येक में केंद्र सरकार के बजटीय पूंजीगत व्यय में 1/4-1/3 की वृद्धि हुई है, जिसमें सार्वजनिक वस्तुओं के अवसंरचना के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। इसने महामारी की बार-बार की लहरों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों और युद्ध के कारण विश्व खाद्य और ईंधन आपूर्ति में व्यवधान के कारण उत्पन्न हुई भारी अनिश्चितता के दौर के दौरान कुल निवेश की वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2.45 का अनुमानित पूंजीगत व्यय गुणक (भानुमूर्ति) निर्माण श्रमिकों को मजदूरी आय प्रदान करके और बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित उद्योगों में निजी निवेश को बढ़ाकर, आगामी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि को बढ़ावा देगा। हालांकि, पीआरसी में बनाई गई अतिरिक्त क्षमता संबंधित वैश्विक अनिश्चितताएं, दीर्घकालिक (3 वर्ष) प्रभाव में विलम्ब कर सकती हैं।

सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) या सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) पर आधारित वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति रही है (चित्र 4)। जीएफसी (जीएफसीएफ) पर आधारित औसत (सरल) आईसीओआर 2000-01 से 2003-04 के दौरान 4.5 (4.8) से बढ़कर 2004-05 से 20013-14 के दौरान 5.8 (4.9) हो गया और तत्पश्चात 2014-15 से 2022-23 के दौरान तेजी से घटकर 4.1 (3.6) हो गया।

"समग्र- व्यावहारिक" दृष्टिकोण को कृषि से उद्योग और सेवाओं में श्रमिकों के स्थानांतरण से संबंधित संरचनात्मक मुद्दों के सामाजिक और राजनीतिक रूप से जटिल मुद्दे पर भी लागू किया गया है। जैसा कि सर्वविदित है कि 2/3 जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बसी हुई हैं, 45% ग्रामीण श्रमिक अभी भी कृषि पर निर्भर हैं। संविधान की राष्ट्रीय महत्त्व के विषय सूची में कृषि शामिल है, और इस प्रकार नीति

बनाने का अधिकार राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जिसकी वे रक्षा करती हैं।। लेकिन संरचनात्मक परिवर्तन, रोजगार, उद्योग (जैसे, उर्वरक) और अंतर- राज्य व्यापार के मुद्दे भी केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं। यह मुद्दा जटिल है और इसके लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, परन्तु विखंडन व्यावहारिक प्रतिक्रिया को बाध्य करता है। कई राज्य सरकारों ने कृषि नीति में सुधार किया है, लेकिन कई ने नहीं किया है। अतः, केंद्र सरकार ने संविधान के तहत उपलब्ध नीतिगत हैंडल का उपयोग करने की कोशिश की है। इनमें कृषि व्यापार में प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हेतु तीन महत्वपूर्ण केंद्रीय कानूनों में सुधार शामिल है, ताकि फसल विविधीकरण, फसल से पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और अन्य गैर-फसल संबद्ध गतिविधियों में विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके। समग्र दृष्टिकोण के अन्य तत्वों में जीआई संकेतकों के माध्यम से अद्वितीय स्थानीय फसलों की ब्रांडिंग, स्थानीय बाजारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाजारों का निर्माण (ईएनएएम), जैविक खेती और जैव ईंधन को बढ़ावा देना, तथा गैर- कृषि गतिविधियों की बढ़ोत्तरी हेतु कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल विकास को बढ़ावा देना शामिल है।

चित्र 4: जीएफसीएफ और जीएफसी पर आधारित आईसीओआर

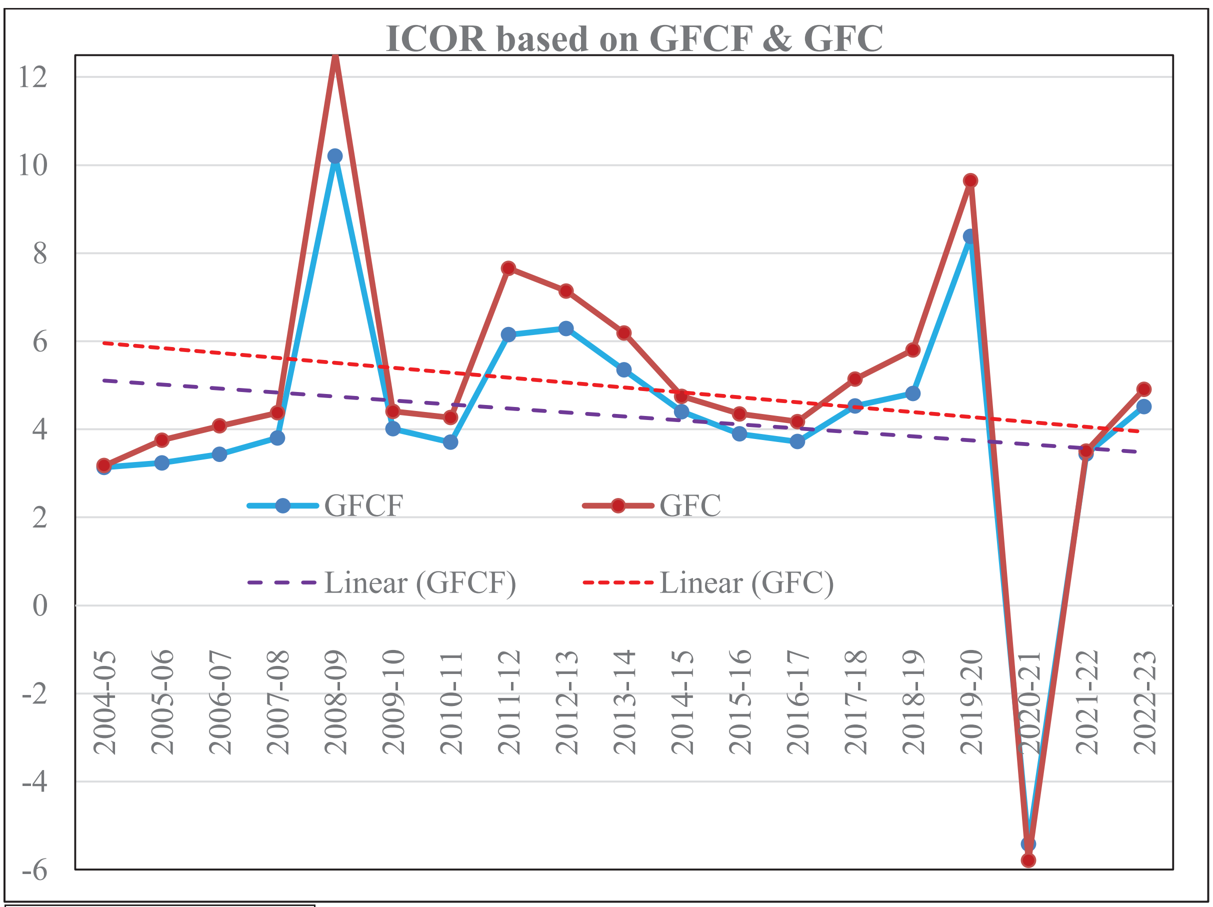

Source: Authors compilation.

तालिका 9: कृषि मूल्य संवर्धन एवं फसल उत्पादकता में वृद्धि (%वार्षिक चक्रवृद्धि)

	Value added	Productivity (yield per hectare)					
	Agri & alied	Rice	Wheat	Coarse Cereals	Pulses	Oilseeds	Sugar cane
fy00-fy04	2.1	1.6	0.9	2.7	1.0	2.4	-3.6
fy05-fy14	3.4	1.6	1.3	3.2	1.20	0.9	1.7
fy15-fy23	3.7	1.8	1.6	3.7	1.24	1.7	2.0
Source: Authors calcualtions based on RBI DBIE data							

इस दृष्टिकोण का परिणाम तालिका 9 में प्रस्तुत किया गया है। पहला कॉलम कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में मूल्य वर्धन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। पिछले 9 वर्षों में यह मामूली रूप से बढ़कर 3.7% हो गई है, जबकि पिछले दस वर्षों में यह 3.4% प्रति वर्ष थी। यह भी दर्शाता है कि इन दो अवधियों में उत्पादकता वृद्धि की दर भी सभी प्रमुख फसलों में बढ़ी है, सबसे अधिक तिलहन में और सबसे कम दालों में वृद्धि हुई है।

घ.4 व्यापार और औद्योगिक नीति

उपलब्ध सीमित ऐतिहासिक साक्ष्यों से हमें ज्ञात हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में, भारत की समृद्धि का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवंतता के साथ सकारात्मक संबंध था। हालाँकि, औपनिवेशिक उद्योग और आय को बढ़ावा देने के लिए व्यापार नीति में हेरफेर करने के औपनिवेशिक अनुभव ने स्थानीय उद्योग को नष्ट कर दिया है, जिसने कई नागरिकों के मन में एक बड़ा सवाल उत्पन्न कर दिया है! इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति स्वायत्तता/आत्मनिर्भरता और खुलेपन के बीच उतार-चढ़ाव करती रही है, इन दो चरम सीमाओं की पृथक परिभाषाएँ प्राथमिकता के लिए संघर्ष करती रही हैं।

मेक इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत और विकसित देशों के साथ एफटीए तक व्यापार नीति का विकास व्यावहारिकता का एक उदाहरण है। कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान (एनआईसी), थाईलैंड और मलेशिया के अनुभव से पता चलता है कि विकास के शुरुआती चरणों में एक व्यापक मुक्त व्यापार नीति को चुनिंदा रूप से बदला जा सकता है, (क) अस्थायी सब्सिडी और टैरिफ संरक्षण दें, बशर्ते इससे मध्यम अवधि में प्रतिस्पर्धा बढ़े (कम न हो), और (ख) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आंतरिक व्यापार नेटवर्क में एफडीआई का महत्व, और निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की बढ़ोत्तरी।

समग्र और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए इस तथ्य की भी सराहना की आवश्यकता है कि, सीसीपी शासित पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) भिन्न है। डब्ल्यूटीओ में शामिल होने के पश्चात, पीआरसी असममित व्यापार (एनटीबी), एफडीआई, प्रौद्योगिकी, ऋण और सब्सिडी नीति के माध्यम से

दुनिया की फ़ैक्टरी बन गयी है। यह एडीपी के 44% हिस्से और दूरसंचार और ऑप्टिकल उपकरणों और अन्य उत्पादों के दसियों हिस्से में 40% हिस्सेदारी में परिलक्षित होता है (तालिका 10)।[25]

विश्व बैंक के एक वर्तमान अध्ययन (अक्टूबर 2023) से पता चलता है कि 2017 और 2022 के बीच, चीन से आयात पर अमेरिकी टैरिफ के कारण सभी वस्तुओं में इसकी हिस्सेदारी में 5.3% अंकों की कमी आई और सामरिक वस्तुओं (जैसा कि यूएसए द्वारा परिभाषित किया गया है) में इसकी हिस्सेदारी में 13.7% अंकों की कमी आई, सभी उत्पादों में अमेरिकी आयात हिस्सेदारी में सबसे अधिक वृद्धि वाले देश वियतनाम (1.9 पीपीटी), ताइवान, चीन (1 पीपीटी), कनाडा (0.75 पीपीटी), मैक्सिको (0.64 पीपीटी), भारत (0.57 पीपीटी) और दक्षिण कोरिया (0.53 पीपीटी) थे। सामरिक वस्तुओं में भारत का लाभ अपेक्षाकृत कम रहा, इसकी रैंक 6 से गिरकर 10 हो गई।

आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव के मामले में भारत की रैंकिंग बढ़ाने के लिए, हमें एक द्वैतवादी व्यापार नीति की आवश्यकता है। एक "द्वैतवादी व्यापार नीति" जो एक ऐसे देश के साथ सम्बन्ध स्थापित करती है जिसने विषम नीतियों के माध्यम से निर्मित निर्यात की एक विस्तृत श्रृंखला पर एकाधिकार कर लिया है, बाकी दुनिया से अलग, एक समग्र और व्यावहारिक दृष्टिकोण के अनुरूप है। द्वैतवादी व्यापार नीति में, उच्च टैरिफ केवल व्यापारिक-एकाधिकार निर्यातक देशों (डब्ल्यूटीओ के लिए राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा छूट के तहत) पर लागू होंगे, लेकिन शेष विश्व (आरओडब्ल्यू) पर नहीं।[26]

[25] उच्च अंक स्तर पर कई उत्पादों के लिए एकाधिकार की मात्रा बहुत अधिक होने की संभावना है।

[26] भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण देश से आयात की एकाग्रता से जोखिम को देखते हुए, राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा कानून/नियमों के तहत उच्च टैरिफ लगाए जा सकते हैं। द्वैतवादी व्यापार नीति, एकाधिकारवादी देशों से आयातित मध्यवर्ती और पूंजीगत वस्तुओं पर अस्थायी रूप से कम टैरिफ के खिलाफ नहीं है, अगर यह भारत में एमएनसी आपूर्ति श्रृंखलाओं के स्थानांतरण में तेजी लाती है। इसके लिए "प्रभावी संरक्षण" के विश्लेषण की आवश्यकता है।

तालिका 10: पी.आर.सी., विश्व का फैक्ट्री या विनिर्माण एकाधिकार?

China's Merchandise Exports, 2021 (% of World exports)	
Product	share
Office machines and automatic data processing machines	36.8%
Automatic data processing machines, n.e.s.	44.0%
Telecommunication and sound recording apparatus	39.0%
Television receivers, whether or not combined	35.9%
Radio-broadcast receivers, whether or not combined	36.6%
Sound recorders or reproducers	36.9%
Telecommunication equipment, n.e.s. ; & parts, n.e.s.	39.9%
Textile yarn and related products	40.8%
Cotton fabrics, woven	48.4%
Fabrics, woven, of man-made fabrics	55.4%
Knitted or crocheted fabrics, n.e.s.	53.8%
Tulles, trimmings, lace, ribbons & other small wares	43.3%
Made-up articles, of texile materials, n.e.s.	48.5%
Miscellaneous manufactured articles	29.4%
Prefabricated building, sanitary, heating and lighting fixture	55.7%
Lighting fixtures & fittings, n.e.s.	67.4%
Travel goods, handbags, etc.	37.2%
Women's clothing, of textile, knitted or croacheted	40.9%
Clothing accessories, of textile fabrics	42.1%
Articles of apparel, clothing access., excluding textile	35.4%
Optical instruments & apparatus, n.e.s.	40.1%
Baby carriages, toys, games & sporting goods	59.0%
Manufactures of metal & non-metalic minerals	28.5%
Cutlery	45.8%
Household equipment of base metal, n.e.s.	57.7%
Pottery	67.4%
machiner & transport equipment	
Household type equipment, electrical or not, n.e.s.	42.7%
Motorcycles & cycles	35.0%
Trailers & semi-trailers	48.5%

स्रोत: लेखक की गणना यूएनसीटीएडी डेटा पर आधारित है

व्यापारिक-एकाधिकार से आयात की अधिकता संबंधी अवसर दिए बिना, व्यापक आयात शुल्क संरचना को सरल बनाने और औसत शुल्कों को कम करने की आवश्यकता है। आयात शुल्क संरचना के सरलीकरण में विशिष्ट शुल्कों को समाप्त करना, आईटीI द्वारा बनाए गए क्रम-भंग शुल्क ढांचे में सुधार, अधिक एकरूपता की ओर कदम और औसत शुल्कों में कमी (चित्र 5) शामिल होगी। इसे प्रमुख

विकसित देशों (यूएसए, ईयू, यूके, जापान) के साथ एफटीए के साथ पूरक किया जाना अपेक्षित है, जिसमें "मूल की संचयी भूमिकाएं" हों।[27]

चित्र 5: प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में सरल औसत आयात शुल्क

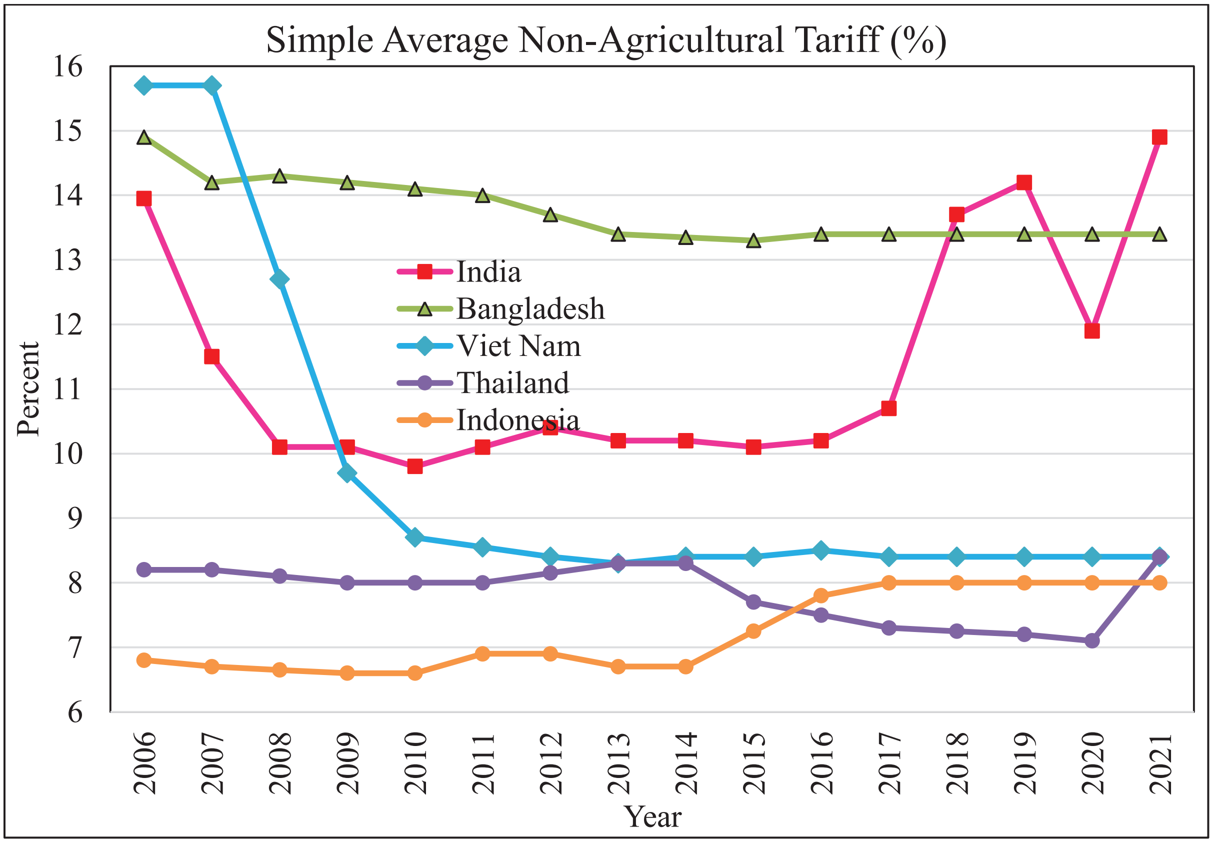

स्रोत: लेखक संकलन

घ.5 अन्य मुद्दे

समग्र, अनुभव- आधारित व्यावहारिकता की एक और अभिव्यक्ति वित्तीय और औद्योगिक विनियमन के दृष्टिकोण में देखी जाती है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले सभी संगठन, जैसे कि सीसीआई, ट्राई, सेबी, आरबीआई आदि को उनके विनियामक लक्ष्यों में पूरी तरह से समर्थन दिया जाता है। हालाँकि, पारंपरिक दृष्टिकोण औद्योगिक संरचना (जैसे, बुनियादी ढांचे) और भारत की विशेष परिस्थितियों (यहां तक कि सबसे बड़ी कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ की तुलना में छोटी हैं) और इसके विकास के चरण में नए विकास के लिए व्यावहारिक रूप से अनुकूलित है।

[27] गैर-कृषि आयातों पर साधारण औसत टैरिफ को घटाकर 10 कर दिया जाना चाहिए, जो 2008 से 2016 तक लागू था, इससे आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव आसान हो जाएगा। चूंकि भारत ने पीआरसी को छोड़कर आरसीईपी के सभी एशियाई सदस्यों के साथ एफटीए किया हुआ है, इसलिए आरसीईपी से बाहर रहने के निर्णय को भी पीआरसी को एफटीए से वंचित करने के व्यावहारिक निर्णय के रूप में देखा जा सकता है।

चूंकि केवल स्थापित, विविधतापूर्ण समूह ही बड़ी, सुस्थापित विदेशी कंपनियों (बुनियादी ढांचे, निर्माण, मैनस्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया) के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक पूंजी जुटा पाते हैं, लंबी अवधि की परियोजनाओं में, जो विनियामक और नीतिगत जोखिम की विशेषता होती है, पूर्व के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ सहायता का प्रावधान प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है (इसे कम करने के बजाय)।[28] एक अन्य उदाहरण आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) है, जहां उच्च स्तरीय शासन देखरेख और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से उसी राज्य में बहुत अधिक विकसित जिलों के साथ विकास अंतर को पाटने में सफलता मिली है।

प्रधानमंत्री मोदी जी इनपुट और नीतिगत बदलावों के सापेक्ष आउटपुट और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके परिणाम अवसंरचना क्षेत्र की (तालिका 11) में देखे जा सकते हैं।

तालिका 11: पिछले दशक में अवसंरचना का विकास

Infrastrucure Development											**Growth(compound)**	
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-1	2021-2	2022-3	(%)	**Years**
Airports-International (nos)				101			140	232	272		**21.9**	fy22/fy17
Highways-National(kms)		91287	97991	101100	114158	126350	132499	136440	140995	144955	**6.0**	fy23/fy15
Rural Roads(Kms)		3304328	3337255	3935337	4166916	4409582	4522228				**6.5**	fy20/fy15
Rail network(000 km)	65	66	66	67	67	67	67	68	68	68	**0.4**	fy23/fy14
Railway electrification	46%	47%	47%	47%	48%	50%	53%	60%			**3.8**	fy21/fy14
Railway accidents(nos)	117	131	106	103	72	59					**-12.8**	fy18/fy14
Ports capacity(mi tonnes)												
Major ports	801	872	965	1066	1452	1514	1535	1561	1598		**9.0**	fy22/fy14
Minor ports	592	803	968	1104	1264	1411	1502	1671			**16.0**	fy21/fy14
Inland waterways: Cargo moved(lakh tons)				415	501	673	719	836	1088		**21.2**	fy22/fy17
Pop using internet(%)	12.3	13.5	14.9	16.5	18.2	20.1	30.0	43.0	46.0		**17.9**	fy22/fy14

सभी नीतिगत सुधारों को निहित स्वार्थी तत्वों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जिन्हें नीतिगत विकृतियों और अनुपयुक्त नीतियों से लाभ मिला है। नीति और संस्थागत सुधार के सापेक्ष निहित स्वार्थी तत्व हैं। इनसे व्यावहारिक तरीके से निपटा गया है, जैसे कि नौकरशाही, राजनीतिक, व्यावसायिक भ्रष्टाचार को कम करने के लिए फॉर्म और अनुपालन का डिजिटलीकरण![29] जिन नीतिगत सुधारों का प्रभावी और समय पर क्रियान्वयन संदेह में है, उन्हें सुधार संबंधी कार्यसूची में नीचे भी रखा जा सकता है, ताकि उस इष्टतम समय का इंतजार किया जा सके जब सफलता की संभावना अधिक हो।

समग्र, अनुभव- आधारित व्यावहारिकता का व्यापक दृष्टिकोण सूचना के अर्थशास्त्र, व्यवहारिक अर्थशास्त्र और सीमित तर्कसंगतता के साथ संगत है और इसके द्वारा उचित ठहराया गया है, अर्थात, मनुष्य के पास सूचना की सीमित उपलब्धता, सोचने की क्षमता और समय की कमी है। यह भारत के अनौपचारिक/

[28] ओयो, ओला और नाइका जैसे स्टार्ट-अप भारत में संचालित समान स्थिति वाले विदेशी स्टार्ट-अप्स के बराबर पूंजी जुटा सकते हैं, लेकिन इसका आंशिक कारण यह है कि उद्यम पूंजी भी बड़े पैमाने पर विदेशी वी.सी. से आ रही है।

[29] यह कई भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों जैसे काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम, रेरा (2016), धन शोधन निवारण संशोधन अधिनियम (2022) की शुरूआत के साथ-साथ चलता है।

असंगठित क्षेत्र के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पूर्ण जानकारी और तर्कसंगत व्यवहार की मान्यताओं पर आधारित सैद्धांतिक निर्माण केवल तभी स्वीकार किए जाते हैं जब उन्हें अनुभवजन्य रूप से सत्यापित किया गया हो या व्यावहारिक अनुभव के अनुरूप हों।

ङ. सशक्तिकरण के माध्यम से प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना

विशेष रूप से डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं की अवधारणा और विकास में भारत पहले से ही डिजिटल सिस्टम के उपयोग में अग्रणी है। लेकिन हम अभी इस यात्रा की शुरुआती चरण में हैं। अगले दशक में समावेशी विकास के भारतीय मॉडल (बीएमआईडी) के विकास का एक प्रमुख तत्व भारत के आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन के लिए डिजिटल और हाइब्रिड (भौतिक- डिजिटल) प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विकास होगा।

भारत में एआई का फोकस विशेषज्ञ प्रणालियों को विकसित करने पर होना चाहिए, जो कम कौशल वाले श्रमिकों को मध्यम-कौशल स्तर पर और मध्यम-कौशल वाले श्रमिकों को उच्च कौशल स्तर पर कार्य-निष्पादन करने में मदद करें। इससे न केवल भारत में कौशल की मांग पूरी होगी, बल्कि भारत विश्व के लिए एक सशक्त कौशल प्रदाता बन जाएगा। यह खंड इस परिवर्तन के कुछ प्रमुख तत्वों और कुछ नीतियों को रेखांकित करता है, जो इसे वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक हैं।

विश्व में कौशल और सामाजिक ई-सेवाओं का आपूर्तिकर्ता बनने के लिए भारत के लिए सार्वभौमिक पहुंच महत्वपूर्ण है। 100% डिजिटल कनेक्टिविटी, सभी गांवों, बस्तियों और सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानों को कवर करती है। सरकारी स्कूलों (पीएस,एसएस), स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी,एसएचसी) और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं (पुस्तकालय) में प्रत्येक गरीब छात्र को निःशुल्क पहुँच। सार्वभौमिक पहुँच बीएमआईडी प्रणाली की नींव बनाएगी ताकि प्रत्येक ज्ञात विभाजन और उससे भी अधिक में अवसर की समानता सुनिश्चित की जा सके।

सामाजिक - व्यावसायिक बाधाओं को तोड़ने से हमारी 1.4 बिलियन जनसंख्या की पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद मिलेगी। घर से काम करना और कहीं से भी काम करना सामाजिक परंपराओं द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है/ किया जाएगा, जो विवाहित महिलाओं की गतिशीलता को प्रतिबंधित करता है और बंद ग्रामीण समुदायों में विशिष्ट समूहों को कुछ प्रकार के काम करने से मना करता है। नीति और संस्थागत सुधारों को सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी बाधाओं को दूर करना चाहिए, और निजी पहल को प्रोत्साहित करना चाहिए। मानसिक बाधाओं को तोड़ने के लिए व्यवहार विज्ञान का उपयोग किया जा सकता है।

ग्रामीण-शहरी एवं अन्य भौगोलिक विभाजनों (जैसे पहाड़ी एवं दूरदराज के क्षेत्र) तथा निम्न सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त करने वाले वंचित समूहों में शिक्षा एवं कौशल की गुणवत्ता को समान बनाना। हाइब्रिड (भौतिक- डिजिटल) प्रणालियों को सर्वोत्तम शिक्षा और कौशल शिक्षकों, शिक्षाविदों (शिक्षाशास्त्र), प्रशिक्षकों और औपचारिक स्तर से नीचे शिक्षण कौशल सहायकों की एक विस्तृत विविधता तक पहुँच प्रदान करके गुणवत्ता के अंतर को कम करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। छात्रों से लेकर शिक्षकों तक शिक्षा के हर स्तर पर कौशल की सेवा गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए डिज़ाइन की गई विशेषज्ञ प्रणालियाँ (एआई) महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सरकार को उचित मानक, प्रमाणन और विनियामक प्रणाली सुनिश्चित करनी चाहिए।

ग्रामीण, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों तथा शहरी झुग्गियों में कई तरह के अयोग्य और कपटी स्वास्थ्य प्रदाता हैं, जो आंशिक रूप से अज्ञानता के कारण रोगियों को निष्फल या हानिकारक उपचार प्रदान करते हैं। ये प्रदाता और उनके रोगी ऑनलाइन विशेषज्ञ प्रणालियों से लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टरों, नर्सों, एएनएम, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों, धर्मशाला देखभाल और स्वास्थ्य, निवारक देखभाल और कल्याण प्रदाताओं की एक विस्तृत विविधता को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके गुणवत्ता अंतर को कम करने के लिए हाइब्रिड प्रणाली तैयार किए जाने चाहिए। सेवा के हर स्तर पर सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ प्रणालियों की एक श्रृंखला तैयार की जानी अपेक्षित है।

सूचना और ज्ञान तक पहुँच असमान है। भले ही हाइब्रिड शिक्षा और नौकरी कौशल प्रणाली युवाओं के बीच असमानता को कम करती है, लेकिन वृद्ध और युवा के बीच का अंतर बढ़ता जाएगा। सूचना प्लेटफॉर्म इस अंतर को कम करके पहुंच को समान बनाने तथा सही समय पर और सही स्थान पर सही सूचना उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सरकारें, गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र और निजी-सार्वजनिक भागीदारी सभी आय और शिक्षा, व्यवसाय (कला, शिल्प) और क्षेत्रों/उद्योगों (कृषि, एमएसएमई, घरेलू उद्यम) के स्तर के आधार पर भूमिका निभाएंगे।

समावेशी विकास के भारतीय मॉडल (बीएमआईडी) का एक प्रमुख तत्व कम्पनियों/निगमों (सार्वजनिक एवं प्रा. लिमिटेड) और अन्य फर्मों (एमएसएमई) के बीच समान अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए एमएसएमई पर लागू सभी करों (जीएसटी, व्यक्तिगत आयकर और आयात शुल्क- निर्यात शुल्क) को डिजिटल बनाने और एकीकृत करने के लिए कर प्रणाली में प्रभावशाली सरलीकरण और सुधार की आवश्यकता है। यह करों, भुगतानों और रिफंड की ऑनलाइन गणना को स्वचालित करेगा, जिससे सभी घरेलू/ एकल मालिक फर्मों के लिए कर अनुपालन का समय और लागत समाप्त हो जाएगी। यह साझेदारी/ एओपी द्वारा लागत और प्रयास को काफी कम करके ईओडीबी में भी सुधार करेगा। ऐसी

प्रणाली को वित्तीय प्रणाली के साथ एकीकृत किया जा सकता है, जिससे एमएसएमई के लिए कार्यशील पूंजी ऋण लगभग स्वचालित हो जाएगा, जिससे दो बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जो एमएसएमई को आधी सदी से परेशान कर रही हैं।

एक एकीकृत, डिजिटलीकृत और वस्तुतः स्वचालित कर प्रणाली, 21वीं सदी के लिए एक अग्रणी, भारतीय कल्याण प्रणाली, शुद्ध आय कर और हस्तांतरण प्रणाली (एनटीटीएस) की शुरूआत के लिए भी मंच तैयार करेगी। एनटीटीएस प्रगतिशील नकद हस्तांतरण प्रणाली को प्रगतिशील आयकर प्रणाली के साथ एकीकृत करेगा, जो राजकोषीय लागत को कम करते हुए काम के लिए प्रोत्साहन को संरक्षित करता है। जिस प्रकार कर की गणना प्रगतिशील आधार पर की जाती है, उसी प्रकार नकद हस्तांतरण भी होगा, जिसमें शून्य आय वाले व्यक्ति को सबसे अधिक हस्तांतरण मिलेगा। जैसे-जैसे आय बढ़ेगी, हस्तांतरण में कमी आएगी, तथा एक बिंदु पर यह शून्य हो जाएगा, तथा कुछ आय सीमा के लिए कर और हस्तांतरण भी शून्य हो जाएंगे। दूसरी सीमा से अधिक आय प्रगतिशील आय के अधीन होगी। यह हस्तांतरण प्रत्येक पात्र वयस्क को आधार सक्षम, पंजीकृत सेल फोन में मोबाइल खाते के माध्यम से स्वचालित रूप से भुगतान किया जाएगा। इस प्रणाली में माँ को नाबालिग बच्चों के कारण नकद हस्तांतरण प्राप्त होगा, साथ ही सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए गरीब महिलाओं को सब्सिडी वाले सेल फोन दिए जा सकते हैं।

अधिकांश विकसित देशों में कार्यशील आयु वाली आबादी का प्रतिकूल पथ, और कुछ मध्यम आय वाले देशों में वृद्धावस्था, तथा भारत की कार्यशील आयु वाली आबादी का बढ़ता वैश्विक हिस्सा एक अनूठा अवसर प्रदान करता है (तालिका 12)। वासुदेव कुटुमबक्कम की अवधारणा के अनुरूप, भारत उच्च आय और उच्चतर मध्यम आय वाले देशों के लिए कुशल और अर्ध- कुशल मजदूर, दोहरे उपयोग और कार्यनीतिक निर्मित वस्तुओं और ऑनलाइन सेवाओं (व्यापार, आर्थिक सामाजिक) की एक विस्तृत श्रृंखला का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बन सकता है। नए अवसरों को प्राप्त करने, खतरों और कमजोरियों को विकास के अवसरों में बदलने के लिए नीति और संस्थागत सुधार महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) में एक विश्वसनीय सुधार एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है, विशेषतः उन राष्ट्रों के लिए जो निजी और विदेशी (एफडीआई) निवेश का स्वागत करने और उन्हें सुकर बनाने के लिए नहीं जाने जाते थे।

तालिका 12: जनसांख्यिकी और तुलनात्मक लाभ

	Country share of World's 20-59 yr olds (WAP)					
		Change in share(%pt)		Share of world WAP (%)		
		2020-1990	2050-2020	1990	2020	2050
1	*High income countries (HICs)*					
2	USA	-1.0	-0.5	5.3	4.2	3.8
3	W Europe	-1.4	-0.6	3.8	2.4	1.8
4	**UK**	-0.3	-0.1	1.2	0.8	0.7
5	Japan	-1.3	-0.6	2.7	1.5	0.9
6	S Korea	-0.2	-0.4	1.0	0.7	0.4
7	Taiwan	-0.1	-0.1	0.4	0.3	0.2
8	*Upper middle income countries (UMICs)*					
9	China	-3.4	-7.8	23.5	20.1	12.3
10	Russia	-1.2	-0.7	3.1	1.9	1.3
11	Thailand	-0.1	-0.4	1.1	1.0	0.6
12	Indonesia	0.3	-0.2	3.3	3.6	3.5
13	Mexico	0.3	-0.1	1.4	1.6	1.5
14	*Lower Middle Income countries (LMICs)*					
15	Viet nam	0.2	-0.2	1.1	1.3	1.1
16	**India**	**2.9**	**0.3**	**15.4**	**18.3**	**18.6**

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुमान नोट: भारत का तुलनात्मक लाभ 2020-2050 के दौरान निम्न कुशल से अर्ध- कुशल और फिर उच्च कुशल की ओर परिवर्तन होगा

च. निष्कर्ष

इस पेपर में भारतीय विकास कार्यनीति का विश्लेषण किया गया है और 'समावेशी विकास के भारतीय मॉडल' पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें इसकी सांस्कृतिक- ऐतिहासिक मूलभूत तत्वों और स्वदेशी विकास दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक भूमिकाओं में परिवार और समुदाय का महत्व शामिल है। मॉडल के उद्देश्य "निरंतर, तेज और समावेशी विकास" हैं, जहां 'समावेशी' का अर्थ है समाज का सर्वांगीण विकास और प्रत्येक नागरिक का सशक्तीकरण, ताकि वह ध्यान और प्रयास के माध्यम से अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का विकास कर सके। इसके अतिरिक्त, यह व्यापार, उत्पादन और निवेश में परिवार और समुदाय की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डालता है, जो उद्यमिता और जोखिम उठाने में योगदान देता है। तदनुसार ,विकास अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से, मॉडल के तीन स्तंभ हैं; अर्थात् भारतीय बाजार अर्थशास्त्र, अंत्योदय और सशक्तिकरण, एवं समग्र दृष्टिकोण।

भारतीय बाजार अर्थव्यवस्था को निजी उद्यमों और बाजार बल के बीच संतुलित पारस्परिक प्रभाव के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है, जिसमें समावेशी विकास और सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चुनिंदा सरकारी अंतःक्षेप होता है। हमारी ऐतिहासिक समाजवादी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, यह दृष्टिकोण साम्यवादी- समाजवादी और अति- पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच एक मध्य मार्ग तैयार करता है। इसी तरह, इस पत्र में विभिन्न संस्थागत, नीतिगत, नौकरशाही और सामाजिक कल्याण सुधारों पर प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने इस दृष्टिकोण का पालन करके पिछले दशक में नियामक अनुपालन को व्यवस्थित रूप से सरल बना दिया है। दूसरा पहलू अंत्योदय और सशक्तिकरण है, दूसरा पहलू अंत्योदय और सशक्तिकरण है, जिसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग और क्षेत्र को सीखने और कमाने के समान अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना है, साथ ही सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और समाज के सबसे वंचित लोगों तक पहुंचना है, जो केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के पुराने तरीकों के विपरीत है। निस्संदेह, इस शोध पत्र ने बहुआयामी गरीबी, महिला कार्यबल भागीदारी दर, लिंग असंतुलन आदि के संकेतकों में सुधार प्रस्तुत किया है। तीसरा पहलू समग्र दृष्टिकोण है, जिसमें अनुभव- आधारित व्यावहारिकता के आधार पर, चिन्हित मुद्दों की सेवा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसी प्रकार, समष्टि आर्थिक प्रबंधन, राजकोषीय नीति, व्यापार एवं औद्योगिक नीति, कृषि नीति, मौद्रिक एवं ऋण नीति को भी इसमें शामिल किया गया है।

नीति और संस्थागत सुधारों के बीच ज्ञात अंतराल को ध्यान में रखते हुए, पिछले 10 वर्षों के दौरान किए गए सुधारों के पूर्ण प्रभाव समय के साथ सामने आएंगे। हालाँकि कुछ परिणाम सामने आ रहे हैं और उन्हें पेपर में विशेष ध्यान दिया गया है। पिछले दशक में शुरू किए गए कई नए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए आगे के विश्लेषण की आवश्यकता है। परिशिष्ट में हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए सुधारों और कल्याणकारी उपायों की सूची प्रस्तुत की गई है, जिनके प्रभाव का विस्तृत शोध के माध्यम से विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

च. संदर्भ

आयोग, नीति आयोग (2023). भारत राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम https://niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/India-National-Multidimentional-Poverty-Index-2023.pdf

भल्ला, एस., भसीन, के., और विरमानी , एम.ए. (2022)। महामारी, गरीबी और असमानता: भारत से साक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/journals/001/2022/069/001.2022.issue-069-en.pdf

भल्ला, एस., भसीन, के., दास, टी., मदरम, ए. (2023 - प्रक्रिया में)। जीवन स्तर परियोजना, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस ODC-BY के तहत विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित अध्ययन।

गोलदार, बी., और अग्रवाल , एससी (2023)। हाल के वर्षों में भारतीय विनिर्माण में रोजगार, उत्पादकता, वास्तविक मजदूरी और श्रम मानकों के रुझान । इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, 1-21. https://link.springer.com/article/10.1007/s41027-023-00442-9

गोलदार, बी., और दास, पीसी (2023)। *भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा: स्थिर या बढ़ रहा है? संरचनात्मक परिवर्तन और आर्थिक गतिशीलता।* *https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.10.004*

गोलदार, बी., दास, पी.सी., और दत्ता , एस. (2023). *भारत के सुधार-पश्चात आर्थिक विकास में सेवाओं की भूमिका। संरचनात्मक परिवर्तन और आर्थिक गतिशीलता।* *https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.10.016*

भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई की सांख्यिकी पुस्तिका, समग्र डेटा (आधार 2011-12)। https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21807

विश्व बैंक, विश्व विकास संकेतक https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

थेंगड़ी, डी. (1995). *थर्ड वे* राष्ट्रोत्थान साहित्य . https://cdn.dbthengadi.in/scan/Tird_way.pdf

यूएनसीटीएडी - व्यापार डेटा. https://unctad.org/statistics

उपाध्याय, डी. (2021) *एकात्म मानववाद: कुछ बुनियादी तत्वों का विश्लेषण* प्रभात प्रकाशन https://www.amazon.in/Integral-Humanism-Analogy-Basic-Elements/dp/9386231751

विरमानी, ए. (1999). *गरीबी से मध्यम आय तक: 21वीं सदी में विकास को गति देने के लिए सुधार।* चिंतन मोनोग्राफ, अप्रैल 1999, ऑनलाइन उपलब्ध है https://icrier.org/pdf/Reform99apr.pdf

विरमानी, ए. (2002). *एक नया विकास प्रतिमान: रोजगार, अधिकारिता और सशक्तिकरण*। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड XXXVII संख्या 22, 1-7 जून, 2002, पृष्ठ 2145-2154. https://doi.org/10.1177/097215090200300205

विरमानी, ए. (2006). भारत का आर्थिक विकास इतिहास: उतार-चढ़ाव। रुझान, ब्रेक पॉइंट और चरण, भारतीय आर्थिक समीक्षा, खंड XXXXI, संख्या 1, जनवरी-जून 2006, पृष्ठ 81-103. (http://www.ierdse.org/).

विरमानी, ए., और हाशिम, एमडीए (2011)। *उत्पादकता और विकास का जे-वक्र: उदारीकरण के बाद भारतीय विनिर्माण* । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11163.pdf

विरमानी, ए. (2012) *विकास को गति देना और बनाए रखना: आर्थिक और राजनीतिक सबक* अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Accelerating-And-Sustaining-Growth-Economic-and-Political-Lessons-26084

विरमानी, अरविंद (2018) *"निवेश: कॉर्पोरेट भारत और भारतीय परिवार,"* वर्किंग पेपर नंबर 1/2018, जून 2018। *निवेश: कॉर्पोरेट भारत और परिवार | ईग्रो फाउंडेशन* ;

विरमानी, ए. (2019). *मंदी को दूर करने और जीडीपी वृद्धि में तेजी लाने के लिए नीतिगत सुधार*। वर्किंग पेपर नंबर 1/2019, फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर, अगस्त 2019। https://egrowfoundation.org/research/policy-reforms-for-reversing-slowdown-and-accelerating-gdp-growth/

विरमानी, ए. (2020). *ग्रोथ रिकेसन: जे कर्व ऑफ़ इंस्टीट्यूशनल रिफ़ॉर्म* वर्किंग पेपर नंबर 1/2020, फ़ाउंडेशन फ़ॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफ़ेयर, फ़रवरी 2020. https://egrowfoundation.org/research/growth-recession-j-curve-of-institutional-reform/

विरमानी, ए. (2021). *इंडिया विज़न 2050.* पॉलिसी पेपर नंबर 1/2021, फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर, मई 2021. https://egrowfoundation.org/research/india-vision-2050/

विरमानी, ए. (2023ए)। *समावेशी विकास का भारतीय मॉडल- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास* एनआईटीआई पॉलिसी पेपर - मई 2023। https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-06/NITI_policy-paper_BMID_2023-may.pdf

विरमानी, ए. (2023बी)। "*सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास समावेशी विकास का भारतीय मॉडल*", अप्रैल 2023 (संशोधित जून 2023), ईजीआरओडब्ल्यू नीति पत्र। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास : समावेशी विकास का भारतीय मॉडल | EGROW फाउंडेशन

परिशिष्ट 1: नीति एवं संस्थागत सुधार: 2014-23

<u>उत्पाद एवं सेवा बाज़ार</u>

- एफडीआई उदारीकरण: इक्विटी सीमाएं
  - रक्षा में 100% तक वृद्धि (74% स्वचालित)
  - बीमा में 74% तक वृद्धि
  - एकल ब्रांड खुदरा (और ई-कॉमर्स): 51% निःशुल्क, 30% घरेलू सोर्सिंग के साथ 1005 ।
- पेट्रोल, डीजल, केरोसीन और एलपीजी की कीमतों का अविनियमन (लक्षित सब्सिडी)
- रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 जिसका उद्देश्य रियल एस्टेट को विनियमित करना तथा रियल एस्टेट लेनदेन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
- डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएँ: ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म
  - जेम - गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, डिजिटल गवर्नमेंट से प्लेटफॉर्म (जी2बी)
  - राष्ट्रीय कृषि बाजार(ई-नाम), एसएफएसी द्वारा प्रबंधित।
- कृषि सुधार
  - कृषि: आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम प्रस्तावित
  - कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (पी एंड एफ) अधिनियम प्रस्तावित।
  - मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक समझौते का प्रस्ताव।
  - वापस लिया गया: इससे किसानों की आय औसतन 38% बढ़ सकती थी, कुछ स्थानों पर 50% तक बढ़ सकती थी।
- उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन 2020-21: रणनीतिक विकास वाले क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना जहां भारत को तुलनात्मक लाभ है।
- सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021: त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रक्रिया, “बच्चा” = 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति
- निरसन एवं संशोधन अधिनियम (2015), अप्रचलित कानूनों (245) का निरसन एवं संशोधन (दूसरा) अधिनियम (2015)। लगभग 1500 पुराने कानून निरस्त किए गए। 40,000 अनुपालन कम/सरल किए गए।
- जन विश्वास विधेयक (2022) में 42 केंद्रीय अधिनियमों के तहत दंडात्मक प्रावधानों को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव है।
- विद्युत (संशोधन) विधेयक: वितरण सुधार।
  - उपभोक्ता विकल्प; उद्योग: उद्योग पर कर समाप्त करें।
- रणनीतिक उद्योग नीति (2020)
  - निजीकरण के लिए रूपरेखा
- राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (2022)।

- ड्रोन उपयोग नियम और ड्रोन सेवा नीति।
- राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति (2023)।

<u>अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स</u>

- गति -शक्ति: मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2020); लॉजिस्टिक्स लागत को आधा करना
    - लॉजिस्टिक्स हब
- राष्ट्रीय राजमार्ग: भारत माला, एनएचडीपी
- रेलवे: समर्पित माल गलियारा, निजी पर्यटक रेलगाड़ियां, स्टेशन
- मेट्रो शहरों के लिए जन परिवहन प्रणालियाँ:
- बंदरगाह: निजी छोटे बंदरगाह और मछली पकड़ने के बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाहों में निजी बर्थ और अन्य सेवाएं
- हवाई अड्डे: निजी हवाई अड्डे (पीपीपी) और निजी सेवाएं
- जलमार्ग, नदी बंदरगाह और जेटी, मालवाहक जहाज, क्रूज जहाज

<u>प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण</u>

- भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम ने कुछ हद तक नौकरशाही को समाप्त कर दिया।
- प्राकृतिक संसाधन नीलामी (तेल, कोयला, खनिज, स्पेक्ट्रम)
    - निजी बोलीदाताओं के लिए खुला
- दूरसंचार स्पेक्ट्रम नीलामी
- पर्यावरण: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, बीएस6 मानदंड, इलेक्ट्रिक वाहन नीति
- खनन एवं खनिजों पर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया; निजी प्रतिस्पर्धा शुरू की गई।
- निजी क्षेत्र कोयला, तेल; रक्षा; अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन, सौर ऊर्जा को बढ़ावा,
    - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन.
- राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (जल विज्ञान संबंधी पद्धतियों में सुधार के लिए बहुआयामी परियोजना, 1995 में शुरू हुई और 2016 में विस्तारित हुई)।
- फेम इंडिया (भारत में इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों का तेजी से अपनाना और विनिर्माण योजना, 2015)।

<u>कारक बाजार: श्रम, पूंजी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन</u>

- भारत दिवाला कोड (आईबीसी): प्रबंधन में प्रतिस्पर्धा, बाजार उन्मुख खराब ऋण समाधान प्रक्रिया
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) सुधार: आरबीआई द्वारा किए गए इन सुधारों से कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और आवास जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में सुधार होगा।
- डिजिटल वित्त:
    - मोबाइल भुगतान, वॉलेट और बचत खाते।
    - एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)
    - बैंकिंग और वित्त के लिए केवाईसी में आधार को शामिल किया गया
    - विनियामक द्वारा फिनटेक को अनुमति दी गई
- शिक्षा नीति (मेडिकल सहित): निजी एवं विदेशी प्रवेश, 0-5 वर्ष के लिए समावेशन।
    - राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान, 2018 को शामिल करने वाले स्कूलों की समग्र प्रभावशीलता में सुधार करना),
    - विश्व स्तरीय संस्थान योजना (उत्कृष्ट संस्थान बनाने का लक्ष्य, 2017),
    - राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों को सुदृढ़ बनाना (स्टार्स, 2020)
- प्रयास करके सीखने की सुविधा के लिए प्रशिक्षुता अधिनियम में संशोधन;
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
    - ई-कौशल मंच
- स्टार्टअप इंडिया; टेक स्टार्टअप: आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण नौकरियाँ।
- श्रम संहिता (4<=44/29):
    - 25/29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने कार्यान्वयन के लिए लिखित नियम बनाए हैं
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (2) का निजीकरण स्वीकृत।
- बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम (1969): 50 वर्ष पुराने अधिनियम में सुधार किया जाना है
- पीएसबी विनियामक जोखिम (सीएजी)
- एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एएमसी
- आईडीबीआई निजीकरण
- बीमा
    - जीआईसी की ¼ कम्पनियों का निजीकरण स्वीकृत।
    - एलआईसी विनिवेश स्वीकृत।

<u>समष्टि अर्थशास्त्र: राजकोषीय, मौद्रिक, बीओपी</u>

- मौद्रिक नीति समिति: लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण।
- वस्तु एवं सेवा कर (संवैधानिक संशोधन)
- कॉर्पोरेट कर सरलीकरण: कटौतियों को समाप्त करने के साथ-साथ दर में कमी तथा दर को घटाकर 25% करना।
    - विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए 3 वर्षों के लिए निम्न दर (15%)।
- पीआईटी डिजिटलीकरण एवं रिटर्न की स्वचालित सीडिंग।
- पीआईटी सरलीकरण: कम दर, कोई कटौती विकल्प नहीं
- सरकारी ई-बाज़ार (जेम)
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), डीसीटी-किसान
- ई- गवर्नेंस : नियमों और प्रपत्रों तक ऑनलाइन पहुंच; प्रपत्रों और अनुपालनों का डिजिटलीकरण
- यूआईडी/ आधार लागू किया गया। कल्याणकारी योजनाओं पर लागू किया गया,
    - वित्तीय क्षेत्र तक विस्तारित (केवाईसी) ।
- विनियामक प्रभाव आकलन (आरआईए): मसौदा रूपरेखा विकसित की गई। विनियमन की राष्ट्रव्यापी लागत (सीओआर) सर्वेक्षण प्रस्तावित
- परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण
    - बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों को अलग करना (हवाई अड्डा, बंदरगाह, रेलवे, जलमार्ग)
    - निजी सेवा एवं प्रबंधन (पीपीपी)
    - राजमार्ग (एनएचएआई)
    - गैस पाइपलाइन (गेल): प्रत्यक्ष पहुंच, सार्वजनिक वाहक
    - शहरी अवसंरचना: खेल स्टेडियम (=> निजी प्रबंधन)

परिशिष्ट 2: सामाजिक कल्याण उपाय

<u>गरीबी उन्मूलन एवं समावेशन</u>

- दीनदयाल अन्त्योदय योजना (मूल रूप से 2011 में एनआरएलएम के रूप में शुरू की गई, 2015 में एसजीएसवाई के साथ समेकित),
- 2/3 जनसंख्या के लिए सब्सिडीयुक्त भोजन (एनएफएसए (2013), 2014-19 में सुधार हुआ)।
    - महामारी के दौरान 50% शहरी और 75% ग्रामीण निवासियों को मुफ्त अनाज प्रदान किया गया

- पीएम पोषण शक्ति निर्माण अभियान (पीएम-पोषण, समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना, स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त दोपहर का भोजन, 1995 का संशोधित संस्करण, 2021 में शुरू किया गया)
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, आरजीएसए (राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ग्रामीण विकास, 2018), स्वामित्व योजना (ग्रामीण विकास, 2020), संसद आदर्श ग्राम योजना, एसएजीवाई, सांझी, सांसद आदर्श ग्राम योजना (आदर्श गांवों का विकास करने के लिए, 2014)
- पीएम जन विकास कार्यक्रम पीएमजेवीके, पीएम जन प्रगति कार्यक्रम , (बहु- क्षेत्रीय विकास, 2018)
- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत (नल, संरक्षण और बाढ़ को कम करने सहित शहरी जल पारिस्थितिकी तंत्र को कवर करने के लिए जल आधारित परियोजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन-2005 से पहले 2015 में लॉन्च किया गया)।

<u>बुनियादी ज़रूरतें:</u>

- ईंधन: हर किसी को-हर जगह -एलपीजी (उज्जवला योजना)
- आवास: पीएम आवास योजना - ग्रामीण और शहरी (सभी के लिए आवास, मूल रूप से 1985 में शुरू की गई, 2015 में संशोधित)।
- बिजली:
    - पीएम सौभाग्य : सहज बिजली हर घर योजना (सार्वभौमिक बिजली कनेक्शन, 2017),
    - दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (ग्रामीण विद्युतीकरण, 2015; 2005 में प्रारंभ),
    - सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (ऊर्जा की बचत और उत्सर्जन में कमी के लिए बचत लैंप योजना, 2015 को प्रतिस्थापित किया गया)।

<u>सार्वजनिक स्वास्थ्य</u>

- स्वच्छ भारत मिशन
    - निजी शौचालय, स्कूल शौचालय, सार्वजनिक शौचालय,
    - स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, सीवेज उपचार
- जल जीवन योजना (स्वच्छ पेयजल),
    - हर घर नल (ग्रामीण घरों के लिए नल का पानी),
    - अटल जल (अटल भूजल योजना, 2019), नमामि गंगे कार्यक्रम (गंगा नदी की सफाई एवं संरक्षण, 2014),

<u>व्यक्तिगत स्वास्थ्य</u>

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति:

    - आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी); डिजिटल मिशन (एबीडीएम)
    - व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी)
    - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)
    - पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र पीएमबीजेके (पीएम भारतीय जन औषधि योजना, 2015)
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का अधिनियमन
- स्वास्थ्य बीमा: गरीबों के लिए सब्सिडी वाला बीमा। पीएमजेएवाई, जन आरोग्य, आयुष्मान भारत, पीएम सुरक्षा बीमा योजना।

<u>बुनियादी शिक्षा और नौकरी कौशल</u>

- कौशल भारत मिशन: व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम (40 करोड़ प्रशिक्षित):
    - जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना
    - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
    - राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)
    - भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्रों (आईआईएससी) का विकास
    - उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (एवीटीएस)
    - आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प)
    - पीएम कौशल विकास योजना (कौशल विकास योजना, 2015),
    - किशोर बालकों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सक्षम , कौशल विकास, 2014),
    - दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, डीडीयू-जीकेवाई, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनाएं, (कौशल विकास, 2014)
- राष्ट्रीय कैरियर सेवा (2015), गरीब कल्याण रोजगार अभियान (गरीब कल्याण रोजगार अभियान, 2020)

<u>वित्तीय समावेशन</u>

- जैम त्रिमूर्ति, जन धन बैंक अधिनियम
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच, स्वाभिमान की जगह 2014 में शुरू की गई), अटल पेंशन योजना (लोगों के स्वैच्छिक योगदान के आधार पर, 2015), पीएम सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, दुर्घटना बीमा के लिए, 2015), पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई, जीवन बीमा योजना, 2015), पीएम श्रम योगी मानधन (असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा और स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से

और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 60 के बाद मासिक पेंशन। एलआईसी और सीएससी द्वारा 2019 में कार्यान्वित)

- सुकन्या समृद्धि योजना (बालिका समृद्धि योजना, 2015), महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र (एमएसएससी, महिला वित्तीय सशक्तिकरण, 2023), पीएम मातृत्व वंदना योजना (प्रधानमंत्री मातृत्व सहायता योजना, 2010 में शुरू की गई, 2017 में इसका नाम बदला गया)

सशक्तिकरण

- भारत नेट (डिजिटल कनेक्टिविटी, चरण I: 2011-17, चरण II: 2017 से आगे), डिजिटल इंडिया (आधार, बीबीएनएल, सीएससीएस, भीम, डिजिटल एम्स, ई-पंचायत, 2015 सहित)
- देश में कहीं भी, प्रत्येक नागरिक के लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी (गति शक्ति)
    - राजमार्ग (अंतरराज्यीय) एवं ग्रामीण सड़कें
    - रेलवे: गलियारे, उच्च गति, बेहतर गुणवत्ता
    - हवाई संपर्क: हवाई अड्डे
    - जल संपर्क: अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग, क्रूज जहाज
    - शहरी मेट्रो: जन परिवहन रेल
- प्रत्येक समूह/उप-समूह (महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदि) के बीच उद्यमशीलता को सुविधाजनक बनाना।
    - अटल नवाचार मिशन: एटीएल (टिंकरिंग लैब्स), एआईसी (नवाचार केंद्र)।
    - मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), महिला उद्यमियों को बढ़ावा
    - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए लक्षित सब्सिडी योजनाएं (गुणवत्ता, एमएसएमई-जेडईडी, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण)

परिशिष्ट 3: शब्दावली

आधार : बच्चों और शिशुओं सहित प्रत्येक भारतीय व्यक्ति के लिए 12 अंकों की विशिष्ट पहचान।

गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)

एपीएल परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार 100% आर्थिक लागत पर 10 किग्रा से 20 किग्रा खाद्यान्न मिलता है।

एस्पायर: ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों और उद्यमों के विकास के लिए योजना।

अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी)

इन केंद्रों का उद्देश्य विश्व स्तर के नवाचार, गतिशील उद्यमियों को बढ़ावा देना और समर्थन देना है जो स्केलेबल और सतत उद्यम बनाना चाहते हैं।

अटल नवाचार मिशन (एआईएम)

हमारे देश के कोने-कोने में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को सृजित करने और बढ़ावा देने के लिए योजना।

अटल न्यू इंडिया (एएनआई)

इस योजना का उद्देश्य अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकियों पर आधारित उत्पाद/समाधान बनाने के लिए नवप्रवर्तकों को समर्थन देना है।

अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल)

अटल टिंकरिंग लैब योजना, जो देश भर में चिन्हित स्कूलों में गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करती है, जहां युवा मस्तिष्क सामाजिक समस्याओं के लिए अपने विचारों को आकार दे सकते हैं।

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)

समुदाय में निम्न आय वाले ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए योजना, जिन्हें सरकार से तत्काल सहायता की आवश्यकता है।

भारत लैंप योजना (बीएलवाई)

भारत में ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा विकसित एक बाजार परिवर्तन योजना।

चुनौती

इस योजना का उद्देश्य कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता का निर्धारण करना था। सबसे कमजोर विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षकों द्वारा उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

कॉयर विकास योजना (सीवीवाई)

उत्पादन इकाइयों को आधुनिक अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने की योजना, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार होगा तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीटीपी) और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन (एनएपी)।

घरेलू उद्योग के लिए विभिन्न व्यवसायों में कुशल श्रमिकों का निरंतर प्रवाह, व्यवस्थित प्रशिक्षण द्वारा औद्योगिक उत्पादन को गुणात्मक रूप से बढ़ाना।

डिजी लॉकर

ड्राइवर लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और शैक्षणिक अंक-तालिका आदि जैसे विभिन्न दस्तावेजों के डिजिटल संस्करण तक पहुंच के लिए पोर्टल।

दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई)

इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से सतत आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर शहरी गरीब लोगों का उत्थान करना है।

ई- पाठशाला

शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों के लिए शैक्षिक संसाधनों का पोर्टल।

बड़ी चुनौतियां

भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के लिए एक साझेदारी ढांचा

सरकारी ई -मार्केट (जेम)

विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए वन स्टॉप पोर्टल

राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक (एनएचएस)

प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र में निजी अस्पतालों और निजी चिकित्सकों को शामिल करने की योजना।

इंडिया स्टैक

इंडिया स्टैक का तात्पर्य भारत की आबादी को डिजिटल युग में लाने के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाने की परियोजना से है।

भारत कृषि मंच (आईएपी) और किसान पोर्टल

कृषि, कृषक बीमा, भंडारण, फसल, विस्तार गतिविधियां, बीज, कीटनाशक, कृषि मशीनरी से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) और हर घर जल (एचजीजे)

2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं।

जनधन - आधार -मोबाइल (जैम)

जन धन खातों, आधार कार्ड और मोबाइल नंबरों को जोड़कर सरकारी सब्सिडी के रिसाव से निपटने की योजना।

जन शिक्षा संस्थान (जेएसएस)

उन कौशलों की पहचान करके जिनका उस क्षेत्र में प्रासंगिक बाजार है, निरक्षरों, नव-साक्षरों के साथ-साथ स्कूल छोड़ने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना ।

महिला कॉयर योजना (एमसीवाई)

इस योजना का उद्देश्य घरेलू और निर्यात बाजारों का विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण, रोजगार/उद्यमिता सृजन करना है।

एमएसएमई: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

मुद्रा

इस योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमियों और गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)

यह व्यवस्था कौशल प्रदान करने वाले उद्यमों, कंपनियों और संगठनों को वित्त पोषण उपलब्ध कराकर कौशल विकास में उत्प्रेरक का काम करती है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)

यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा कृषि उपज से मंडियों को जोड़ता है।

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी)

देश में डिजिटल वाणिज्य इकोसिस्टम में क्रांति लाने के लिए पोर्टल।

ऑनलाइन लैब्स

ऑनलाइन प्रयोगशालाएं उन छात्रों के लिए उपलब्ध हैं जिनके पास भौतिक प्रयोगशालाओं तक पहुंच नहीं है या जहां उपकरण दुर्लभ या महंगे होने के कारण उपलब्ध नहीं हैं।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)

यह योजना लाभार्थी को सेवा स्थल अर्थात अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक नकदी रहित पहुंच प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

एक वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना जो हर साल नवीनीकृत की जा सकती है तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है

पीएम कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

भारतीय युवाओं के लिए उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने की योजना, जिससे उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री जन- धन योजना (**पीएमजेडीवाई)**

योजना - राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन, जिसका उद्देश्य किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं अर्थात बुनियादी बचत एवं जमा खाते, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री पोषण (पीएमपी)

सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों आदि में कक्षा I-V तक के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए योजना।

प्रधानमंत्री पोषण सौभाग्य योजना (पीएमपीएसवाई) और सहज बिजली योजना (एसबीवाई)

ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और सभी अविद्युतीकृत घरों को बिजली कनेक्शन देने की योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)

वर्ष 2024 तक शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने की योजना

स्वच्छ भारत मिशन

भारत सरकार द्वारा देश की गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को साफ करने के लिए 4041 वैधानिक शहरों को कवर करने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान।

समृद्ध

स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना ताकि वे सफल हो सकें।

स्किलिंग इंडिया

यह पोर्टल भारतीयों में कौशल निर्माण की योजनाओं पर केंद्रित है, जिससे राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान बढ़ेगा।

सशक्त

एक शिक्षा पोर्टल, भारत में शिक्षण और सीखने के तरीके को बदल देगा।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब परिवारों को स्वरोजगार अपनाने में सहायता प्रदान करना

उदयम

नया एमएसएमई पंजीकृत करने या पहले से पंजीकृत ईएम-II (उद्यमी ज्ञापन, भाग-II) या यूएएम (उद्योग आधार ज्ञापन) को पुनः पंजीकृत करने के लिए पोर्टल

उज्ज्वला योजना

महिलाओं और परिवारों के स्वास्थ्य को एलपीजी के रूप में स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराकर अस्वास्थ्यकर ईंधन के उपभोग से बचाने की योजना।

उन्नत ज्योति योजना (यूजेवाई)

घरेलू उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर ऊर्जा कुशल एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की योजना।

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई)

एक ऐसी प्रणाली जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में अनेक बैंक खातों को संचालित करती है।

योजना = स्कीम